▪ मार्गशीर्ष कृष्णा - 13 ▪ संवत 2081 ▪ वर्ष - 20 ▪ अंक - 125 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- बेंगलूरु » शुक्रवार » 29-11-2024 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 भारत अगले 10 वर्षों में फीफा रैंकिंग में शीर्ष 50 में पहुंच सकता है : मांडविया

6 बाल विवाह मुक्ति बेटियों को खुला आसमान देगा

7 सुमित कौल 'तेनाली रामा' में गिरगिट की भूमिका में आयेंगे नजर

फर्स्ट टेक

श्रमिक कल्याण कोष बढ़ाने के लिए कर्नाटक मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी

बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक श्रमिक कल्याण कोष (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे श्रमिक कल्याण कोष में वृद्धि होगी। कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि विधेयक पारित होने के बाद, श्रमिक का हिस्सा 50 रुपए, नियोक्ता का हिस्सा 100 रुपए और सरकार का हिस्सा 50 रुपए होगा। उनके अनुसार, अबतक श्रमिक का योगदान 20 रुपए, नियोक्ता का 40 रुपए और राज्य सरकार का 20 रुपए था। पाटिल ने कहा, ''यह कर्नाटक श्रमिक कल्याण कोष में जाएगा। इससे कोष को बड़ा बनाने में मदद मिलेगी।''

भारत, रूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास का विस्तार करने का निर्णय

नई दिल्ली/भाषा। भारत और रूस ने परिचालन तालमेल को और मजबूत करने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास का विस्तार करने का फैसला किया है। यह निर्णय भारत-रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग आयोग (आईआरआईजीसी-एमएंडएमटीसी) के तहत सैन्य सहयोग पर कार्य समूह की इस सप्ताह हुई बैठक में लिया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बैठक ''दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई।'' उसने कहा, ''इसमें दोनों सेनाओं के बीच परिचालन तालमेल को और मजबूत करने के लिए संयुक्त अभ्यास का विस्तार करने पर भी सहमति बनी।''

पूर्वी युगांडा में भूस्खलन से 40 घर नष्ट, कम से कम 15 लोगों की मौत

नैरोबी/एपी। पूर्वी युगांडा के छह गांवों में भूस्खलन के कारण कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई तथा 113 अन्य लापता हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार 15 घायल लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युगांडा रेड क्रॉस सोसाइटी ने बृहस्पतिवार को बताया कि भूस्खलन में 40 घर नष्ट हो जाने के बाद 13 शव बरामद किए गए तथा बचाव कार्य अभी जारी है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़कर 30 तक हो सकती है। बुधवार रात भारी बारिश के बाद पहाड़ी जिले बुलाम्बुली में भूस्खलन हुआ। यह जिला राजधानी कंपाला से लगभग 280 किलोमीटर पूर्व में है।

सूर्यास्त 28-11-2024 5:50 बजे	सूर्योदय 29-11-2024 6:25 बजे
BSE 79,043.74 (-1,190.34)	NSE 23,914.15 (-360.75)
सोना 7,981 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	चांदी 90,517 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक

epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

पाँच साल के हाल

पहला बीते जयकारों में,
दूजे में करते कदमताल।
तीजे में करे घोषणाएं,
मुद्दे की बातें टाल-टाल।
चैथे में फैंकेंगे दाने,
अपने हित में कुछ बचा माल।
अंतिम में फिर वादे दे कर,
पूरे कर देते पाँच साल।।

साइबर युद्ध, जलवायु परिवर्तन जैसी

भविष्य की चुनौतियों से निपटने को तैयार रहना होगा भारत को : राष्ट्रपति

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

उधगमंडलम (तमिलनाडु)/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को यहां कहा कि भारत को तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें साइबर युद्ध और आतंकवाद जैसी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां शामिल हैं। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय और वैश्विक परिदृश्यों की गहरी समझ विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया क्योंकि भू-राजनीतिक गतिशीलता ने सुरक्षा परिदृश्य को बदल दिया है।

नीलगिरी जिले के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा, ''जलवायु परिवर्तन का मुद्दा एक नया आयाम प्राप्त कर रहा है, जिसे समझने और प्रबंधित करने की आवश्यकता है। नवीनतम अत्याधुनिक तकनीक को लागू करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि हमारे सशस्त्र कार्मिक अधिकारी भविष्य की चुनौतियों का सामना करेंगे।''

मुर्मू ने कहा, ''तेजी से बदलते भू-राजनीतिक माहौल में हमें किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार रहना होगा।'' उन्होंने कहा, ''भू-राजनीतिक गतिशीलता ने सुरक्षा परिदृश्य को बदल दिया है और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्थितियों की गहरी समझ विकसित करने की आवश्यकता है। हमें न केवल अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना है, बल्कि साइबर युद्ध और आतंकवाद जैसी नई राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना है।''

मुर्मू ने कहा कि भारत आगे बढ़ रहा है और दुनिया रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश की भूमिका को स्वीकार कर रही है। उन्होंने कहा कि देश सशस्त्र बलों की जरूरतों और चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को एक प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और यह एक विश्वसनीय रक्षा भागीदार और रक्षा निर्यातक बनने की ओर बढ़ रहा है।

दिल्ली के प्रशांत विहार में पीवीआर के पास विस्फोट, एक व्यक्ति घायल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली के रोहिणी में पीवीआर प्रशांत विहार के पास बृहस्पतिवार को कम तीव्रता का विस्फोट हुआ जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

यह विस्फोट उसी इलाके में एक पार्क के पास एक मिठाई की दुकान के सामने हुआ जहां 20 अक्टूबर को सीआरपीएफ स्कूल की एक दीवार भीषण विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो गई थी।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि पूर्वाह्न 11:47 बजे प्रशांत विहार में बंसी वाला मिठाई की दुकान के सामने विस्फोट होने की सूचना मिली।

बम का पता लगाने वाली टीम, खोजी कुत्ते, पुलिस और दमकल कर्मियों के मौके पर पहुंचने के तुरंत बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई।

मौके से सफेद पाउडर बरामद हुआ।

इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से बांग्लादेशी अदालत का इनकार

ढाका/भाषा। बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को देश में इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक याचिका खारिज कर दी। सुरक्षाकर्मियों और एक हिंदू धार्मिक नेता के समर्थकों के बीच झड़प में एक वकील के मारे जाने के कुछ दिन बाद एक वकील ने अखबारों में इस्कॉन से जुड़ी कुछ खबरों को संदर्भित करते हुए संगठन पर प्रतिबंध की मांग करते हुए बुधवार को याचिका दायर की थी।

अटॉर्नी जनरल कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ''न्यायमूर्ति फराह महबूब और न्यायमूर्ति देबाशीष रॉय चौधरी की दो सदस्यीय पीठ ने बृहस्पतिवार को बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया।'' उन्होंने कहा कि पीठ ने यह निर्णय अटॉर्नी जनरल कार्यालय द्वारा इस सप्ताह के शुरू में पूर्वोत्तर बंदरगाह शहर चटगांव में सहायक सरकारी अभियोजक सैफुल इस्लाम अलीफ की मौत के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद किया।

वक्फ समिति का कार्यकाल बजट सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ा

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल बृहस्पतिवार को अगले साल बजट सत्र के आखिरी दिन तक के लिए बढ़ा दिया। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने वक्फ (संशोधन) विधेयक संबंधी संसद की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 2025 के आखिरी दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया, जिसे ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की गई। पाल के नेतृत्व में बुधवार को हुई समिति की बैठक में सदस्यों ने इस संदर्भ में एक प्रस्ताव पर सर्वसम्मति व्यक्त की थी। बैठक में एक प्रस्ताव के माध्यम से निर्णय लिया गया कि समिति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह करेगी कि उसका कार्यकाल अगले साल बजट सत्र के आखिरी दिन तक के लिए बढ़ाया जाए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और समिति के सदस्य कल्याण बनर्जी ने कहा कि कार्यकाल बढ़ने से सभी सबंधित लोगों और समूहों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। समिति की अब तक हो चुकीं 25 से अधिक बैठकों में कई मौकों पर पाल और विपक्षी सदस्यों के बीच गतिरोध देखने को मिला है।

झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रांची/भाषा। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को यहां एक भव्य समारोह में राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी समेत 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) गठबंधन के कई नेता मौजूद थे।

झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 49-वर्षीय आदिवासी नेता सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।

सोरेन ने सभी वर्गों, विशेषकर गरीबों, वंचितों और शोषितों के कल्याण के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के तुरंत बाद कहा, ''यह सरकार झारखंड के गरीबों, वंचितों और शोषितों समेत सभी वर्गों के लिए दिन-रात काम करेगी...अबुआ सरकार।''

सोरेन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''आज का यह ऐतिहासिक मौका झारखंड के अमर वीर शहीदों, महान क्रांतिकारियों के संघर्ष को समर्पित है...आज का यह भावुक क्षण झारखंड के करोड़ों लोगों को समर्पित है।'' शपथ लेने से पहले सफेद कुर्ता, पायजामा और 'नेहरू जैकेट' पहने हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और दो बेटों के साथ झामुमो प्रमुख एवं अपने पिता शिबू सोरेन और अपनी मां रूपी सोरेन से आशीर्वाद लिया।

समारोह के बाद उन्होंने बिरसा मुंडा और सिदो-कान्हो जैसे आदिवासी नायकों को पुष्पांजलि अर्पित की और 'प्रोजेक्ट बिल्डिंग' पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी चौथी पारी शुरू की।

अजमेर दरगाह मुकदमे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा

हिंदुओं को सर्वेक्षण की मांग करने का कानूनी अधिकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि हिंदुओं को अदालतों का दरवाजा खटखटाने और मस्जिदों के सर्वेक्षण की मांग करने का अधिकार है क्योंकि यह सच है कि इनमें से कई मस्जिद मुगल आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किए गए मंदिरों के खंडहरों पर बनाई गई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद ऐसे विवादों को खत्म करने के लिए कदम उठाए होते तो हिंदुओं को राहत के लिए अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता।

राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण की मांग को लेकर निचली अदालत में दायर याचिका के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ''इसमें दिक्कत क्या है? यह सच है कि मुगल आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया था मंदिरों के खंडहरों

पर मस्जिद बनाने का अभियान आक्रमणकारियों द्वारा चलाया गया था।''

सिंह ने कहा, ''अगर नेहरू ने आजादी के बाद ऐसे विवादों को खत्म करने के लिए कदम उठाए होते तो आज हमें अदालतों में याचिका दायर करने की जरूरत नहीं पड़ती।'' उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण करना कानूनी अधिकार है। सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल अदालत के निर्देश पर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने सपा सांसद रामगोपाल यादव द्वारा दरगाह और संभल मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिकाओं को ''साजिश'' बताए जाने पर समाजवादी पार्टी की आलोचना भी की।

उन्होंने कहा, ''यह रामगोपाल यादव की पार्टी के डीएनए में है... वे हिंदुओं पर गोली चलाने, उनके अधिकार छीनने की बात करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने ऐसा तब किया था जब वह (उत्तर प्रदेश के) मुख्यमंत्री थे। वे वोट के लिए मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं।''

सिंह ने पूछा, ''हिंदू कहां जाएंगे?'' उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ''हिंदुओं के दमन'' की कोशिश कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''उनके पास अब भी सबक सीखने का समय है। देश का मूड उनके पक्ष में नहीं है।''

राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव ने कहा था कि सर्वेक्षण की मांग को लेकर अदालत में याचिका दायर करना ''देश में आग लगाने की साजिश'' है। उन्होंने संसद परिसर में भाजपा पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, ''लोग सत्ता में बने रहने के लिए देश को नष्ट करना चाहते हैं।''

ट्रंप 'भारत के मित्र', भारत-अमेरिका साझेदारी और मजबूत होगी : गोयल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 'भारत का मित्र' बताते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि उनके कार्यकाल में भारत-अमेरिका की दोस्ती और भी मजबूत होगी।

गोयल ने यह भी कहा कि उन्हें भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी में कोई भी समस्या नहीं दिखती है और आने वाले समय में नए प्रशासन के आने से यह भागीदारी और भी सशक्त होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के 10 वर्षों के शासन में लागू विभिन्न पहलों और सुधारों पर मीडिया से बात करते हुए गोयल ने टेस्ला और स्टारलिंक की निवेश योजनाओं से लेकर लैपटॉप आयात नीति और यूरोपीय संघ के एकतरफा हरित अर्थव्यवस्था नियमों तक के सवालों के जवाब दिए।

ट्रंप के अगला राष्ट्रपति बनने पर भारत के नजरिये के बारे में पूछे जाने पर गोयल ने कहा, मुझे लगता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

भारत में टेस्ला, स्टारलिंक के निवेश पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं

नई दिल्ली/भाषा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की टेस्ला और स्टारलिंक द्वारा भारत में निवेश के संबंध में फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि चूंकि दोनों मुद्दे अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा देखे जा रहे हैं, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है। टेस्ला और स्टारलिंक द्वारा संभावित निवेश के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा, जहां तक मेरी जानकारी है, हमने कोई चर्चा नहीं की है...। गोयल ने कहा, ...लेकिन ये दोनों विषय अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा संभाले जाते हैं। भारी उद्योग मंत्रालय वाहन को देखता है और स्टारलिंक को अंतरिक्ष विभाग द्वारा संभाला जाएगा। इसलिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं पता कि क्या हो रहा है ...।

संघर्ष विराम लागू होने के बाद

इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमला किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेरूत/एपी। इजराइली सेना ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने एक रॉकेट भंडारण इकाई पर हिजबुल्ला की गतिविधि का पता लगने के बाद दक्षिणी लेबनान पर गोलाबारी की। यह इजराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष विराम लागू होने के एक दिन बाद पहला इजराइली हवाई हमला है।

इजराइल के हवाई हमले में हताहतों के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं दी गई, जो इजराइली सेना द्वारा यह कहे जाने के कुछ घंटे बाद किया गया

कि उसने दक्षिणी लेबनान में कुछ क्षेत्रों में लौटने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोलीबारी की। इजराइल ने कहा कि वे युद्धविराम समझौते का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन कोई विवरण नहीं दिया। लेबनान की सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा कि दो लोग घायल हुए हैं।

लगातार हुई घटनाओं ने अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से हुए समझौते को लेकर बेचैनी पैदा कर दी है, जिसमें शुरुआती दो महीने का संघर्ष विराम शामिल है। इसके तहत हिजबुल्ला के लड़ाकों को लिटानी नदी के उत्तर में वापस जाना है और इजराइली सेना को सीमा के अपने हिस्से में वापस लौटना है।

रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर 200 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमले किए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कीव/एपी। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए बृहस्पतिवार को 200 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों के कारण देश भर में 10 लाख से ज्यादा आबादी बिजली से वंचित है। यूक्रेन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

दो सप्ताह से भी कम समय में यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर रूस के दूसरे बड़े हवाई हमले से यह आशंका बढ़ गई है कि रूस का इरादा सर्दी से पहले यूक्रेन की ऊर्जा उत्पादन क्षमता को तहस-नहस करना है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री हर्मन हालुशेंको ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि पूरे यूक्रेन में ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बिजली आपूर्ति बंद की जा रही है।

■ 10 लाख से ज्यादा आबादी बिजली से वंचित

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में, कलस्टर हथियारों से लैस कलिब्र क्रूज मिसाइलों ने नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। कलस्टर हथियार एक बड़े क्षेत्र में कई छोटे बम छोड़ते हैं, जिससे वे हमले के दौरान और उसके बाद नागरिकों के लिए ख़तरनाक हो जाते हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने हाल में कहा था कि रूस ठंड के मौसम से पहले ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने के लिए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार जमा कर रहा है।

रूस के साथ लगभग तीन साल से जारी युद्ध के दौरान यूक्रेन का करीब आधा ऊर्जा बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है, और बिजली की आपूर्ति में लगातार कटौती आम बात है। यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों ने वायु रक्षा प्रणालियों और पुनर्निर्माण के लिए धन के साथ यूक्रेन को बिजली उत्पादन की रक्षा करने में मदद करने की मांग की है।

भारत ने यूरोपीय संघ के कार्बन कर नियमों पर निराशा जताई : गोयल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि यूरोपीय संघ के 'एकतरफा' हरित अर्थव्यवस्था नियमों को अनुचित बताते हुए भारत ने इस पर 'गहरी निराशा' जताई है।

यूरोपीय संघ के प्रस्तावित नियम ईयूडीआर के तहत यूरोपीय बाजार में निर्दिष्ट वस्तुओं का निर्यात करने वाले संचालकों या कारोबारियों को यह साबित करना होगा कि उनके उत्पादों का वनों की कटाई से किसी भी तरह का संबंध नहीं है।

इस कानून के तहत प्रस्तावित कार्बन सीमा समायोजन प्रणाली (सीबीएएम) में ऐसे शुल्क लगाए गए हैं जो यूरोपीय संघ (ईयू) में ऊर्जा का अधिक उत्सर्जन करने वाली आयातित वस्तुओं पर लागू होंगे।

भारत को चिंता है कि इन प्रावधानों की वजह से भारत से सीमेंट, एल्युमीनियम, लोहा और इस्पात जैसी अधिक कार्बन उत्सर्जन वाली वस्तुओं के आयात पर उच्च शुल्क लग सकता है जो ''एकतरफा'' व्यापार अवरोधक के तौर पर काम करेगा।

गोयल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने एक दिन पहले ही फ्रांस की मंत्री के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया था।

गोयल ने फ्रांस की विदेश व्यापार मंत्री सोफी प्रीमस के साथ व्यापार, निवेश तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर बुधवार को चर्चा की थी। गोयल ने यूरोपीय संघ के प्रावधानों की वजह से भारतीय निर्यातकों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला।

जाति सर्वेक्षण : ए रेवंत रेड्डी ने जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों को राज्य में किए जा रहे सामाजिक-आर्थिक और जाति सर्वेक्षण के तहत सांसदों, विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों और अफसरों का विवरण दर्ज करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया।

रेड्डी ने अपने आवास पर अधिकारियों और सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम के साथ अपना विवरण साझा किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हैदराबाद में वीवीआईपी, आईएएस, आईपीएस, सांसदों, विधायकों और अन्य जन प्रतिनिधियों के विवरण को दर्ज करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकारी कर्मचारियों से सर्वेक्षण में अपना विवरण दर्ज कराने के निर्देश जारी करने को भी कहा। उन्होंने अधिकारियों से सर्वे की प्रगति और इस पर जनता की प्रतिक्रिया को लेकर भी जानकारी ली। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 27 नवंबर तक 95 प्रतिशत सर्वेक्षण पूरा हो चुका था। सर्वेक्षण के लिए चिन्हित किए गए 1,18,02,726 घरों में से 1,10,98,360 घरों से विवरण एकत्र किया जा चुका है।

देश में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए परीक्षण सुविधाओं की आवश्यकता: नीति आयोग सदस्य

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। नीति आयोग के सदस्य वी के सारस्वत ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत को अपने महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा बदलाव लक्ष्य को समर्थन देने के उद्देश्य से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त परीक्षण सुविधाएं स्थापित करनी चाहिए।

बयान के अनुसार, फिक्की के ऊर्जा भंडारण सम्मेलन-2024 में उन्होंने परीक्षण और प्रमाणन बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतर को उजागर किया। भारत का लक्ष्य 2030 तक 238 गीगावाट घंटे से अधिक की बैटरी भंडारण क्षमता तैनात करना है ताकि इसके विस्तारित नवीकरणीय ऊर्जा नेटवर्क को संतुलित किया जा सके। उन्होंने सरकार द्वारा भंडारण प्रमाणन एजेंसियां स्थापित किए जाने तक तीसरे पक्ष द्वारा परीक्षण और प्रमाणन को अधिकृत करने का आह्वान किया। सारस्वत ने कहा कि भारत को सभी प्रकार की ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए एक सार्वभौमिक मानक की आवश्यकता है। हालांकि भारतीय मानक ब्यूरो ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए 17 विनिर्देश विकसित किए हैं तथा और भी विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन देश में इन मानकों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। आक्रामक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के बावजूद भारत के ऊर्जा मिश्रण में कोयले महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी। इसकी 2047 में अनुमानित क्षमता 150 गीगावाट होगी, जो वर्तमान में 218 गीगावाट से कम है। 2047 तक सौर क्षमता में पर्याप्त विस्तार होने की उम्मीद है, जिसके लिए व्यापक भंडारण एकीकरण की आवश्यकता होगी।

रोजगार मेलों के दौरान 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अनंतिम रूप से चुना गया: जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोजित रोजगार मेलों के दौरान 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अनंतिम रूप से चुना गया है। राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सिंह ने बताया कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2019-20 से 2023-24 के दौरान पिछले पांच वर्ष में राज्य रोजगार कार्यालयों /मॉडल करियर केंद्रों द्वारा 34,809 रोजगार मेले आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना के हिस्से के रूप में आयोजित किए जाते हैं। सिंह ने कहा कि पांच साल की अवधि में नौकरी के इच्छुक 26,83,161 लोगों और 83,913 नियोक्ताओं ने रोजगार मेलों में भाग लिया।

मेरा नाम का कहीं जिक्र नहीं: अदाणी रिश्वत विवाद पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अमरावती/भाषा। वाईएसआरसीपी के शीर्ष नेता एवं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने उनकी पार्टी नीत सरकार के कार्यकाल के दौरान सौर ऊर्जा खरीद के लिए अदाणी समूह द्वारा राज्य के अधिकारियों को रिश्वत दिए जाने के आरोपों का बृहस्पतिवार को पुरजोर खंडन किया और कहा कि इस मामले में अमेरिकी अदालत के अभियोग में कहीं भी उनका नाम नहीं है।

अदाणी रिश्वत विवाद शुरू होने के बाद पहली प्रतिक्रिया में जगन ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बार अदाणी से मुलाकात की जो ''असामान्य नहीं'' है। जगन ने कहा, ''इसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि मुझे रिश्वत की पेशकश की गई क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मुझे रिश्वत नहीं दे सकता, और कारोबारियों का नेताओं से मिलना कोई असामान्य बात नहीं है बल्कि यह एक सामान्य चलन है।'' रिश्वत के आरोप अफवाह हैं और किसी ने भी यह नहीं कहा है कि जगन या किसी अन्य ने रिश्वत ली है। गौतम अदाणी पर अमेरिकी न्याय विभाग ने अनुकूल सौर ऊर्जा अनुबंधों के बदले भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देने में उनकी भूमिका को लेकर आरोप लगाया है, हालांकि भारतीय समूह ने इस आरोप का खंडन किया है। जगन ने कहा कि वह कुछ स्थानीय दैनिक अखबारों के खिलाफ तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और खबरें प्रकाशित करने के आरोप में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे।

प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने गेमिंग ऐप मामले में गूगल के खिलाफ जांच के आदेश दिए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) ने 'गेम' खेलकर पैसे कमाने से संबंधित ऐप को प्लेस्टोर पर सूचीबद्ध किए जाने के संदर्भ में कथित तौर पर अनुचित व्यापार तरीके अपनाने के मामले में बृहस्पतिवार को गूगल और उसके सहयोगियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए।

आयोग ने अपना आदेश पारित करते हुए कहा कि महानिदेशक को अधिनियम की धारा 26(1) के प्रावधानों के तहत मामले की जांच करने का निर्देश दिया जाता है। आयोग ने महानिदेशक को 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करने और एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही सीसीआई ने स्पष्ट किया है कि आदेश में उसकी टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं और ये उसका अंतिम निर्णय नहीं हैं।

सीसीआई का यह आदेश विंजो गेम्स की शिकायत पर आया है। गेमिंग ऐप ने गूगल पर अपने प्रभावी स्थान का दुरुपयोग करने और चुनिंदा गेमिंग श्रेणियों को अनुचित रूप से अहमियत देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे गेमिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा बाधित हो रही है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि डीएफएस और रम्मी ऐप को प्लेस्टोर पर चुनिंदा रूप से जगह देने से उन्हें अनुचित रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। आयोग ने कहा, प्लेस्टोर के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं तक सीधी पहुंच मिलने से डीएफएस और रमी ऐप को महत्वपूर्ण बढ़त मिलती है, जो संभावित रूप से अन्य कमाई गेमिंग ऐप को नुकसान पहुंचाती है। सीसीआई ने उपयोगकर्ताओं द्वारा आरएमजी ऐप डाउनलोड करने का प्रयास करने पर प्रदर्शित गूगल की साइडलोडिंग चेतावनियों पर भी चिंता जताई। विंजो का कहना है कि ये चेतावनियां उसकी छवि को धूमिल करती हैं और संभावित उपयोगकर्ताओं को इसके ऐप तक पहुंचने से हतोत्साहित करती हैं।

नियामक ने आदेश में कहा है कि एंड्रॉयड परिवेश में गूगल के दबदबे ने प्रतिस्पर्धा-रोधी निष्कर्षों के लिए उसकी नीतियों के आकलन को अनिवार्य बना दिया है। गूगल द्वारा विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड से संचालित सभी फोन में प्लेस्टोर पहले से ही इंस्टॉल होता है। इसके जरिये ही उपयोगकर्ता किसी ऐप को डाउनलोड कर सकता है। आयोग ने कहा कि डीएफएस और रमी से इतर कमाई वाले गेमिंग ऐप को प्लेस्टोर से बाहर करना उन्हें बाजार तक पहुंच देने से इनकार करने के बराबर है।

भारतीय वायुसेना का 'व्हाइट वाटर राफ्टिंग' चमोली से शुरू

गोपेश्वर/भाषा। भारतीय वायुसेना का बृहस्पतिवार को उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा नदी में 'व्हाइट वाटर राफ्टिंग' अभियान शुरू हुआ। अलकनंदा और गंगा नदियों के जलप्रवाह के साथ नावों के जरिए संचालित होने वाला यह अभियान तीन दिसंबर को ऋषिकेश में पूरा होगा। 'एयरफोर्स हेडक्वार्टर एडवेंचर सेल' दिल्ली के तत्वाधान में चमोली में अलकनंदा नदी के घाट से शुरू हुए इस अभियान का वायु सेना के विंग कमांडर विजय भट्ट नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें वायु सेना के 14 जवान एवं दो गाइड शिरकत कर रहे हैं ।

'व्हाइट वाटर राफ्टिंग' के लिए गंगा नदी खासतौर पर उसकी प्रमुख सहायक नदी अलकनंदा नदी की घाटी सबसे चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। विंग कमांडर भट्ट ने बताया कि वायु सेना द्वारा इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं और वायु सैनिकों को

साहसिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे जहां युवा सेना में आने के लिए प्रेरित होंगे वहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गाइड विवेक नेगी ने बताया कि अभियान के दौरान वायु सैनिकों को 'व्हाइट वॉटर रिवर राफ्टिंग' में 'रेस्क्यू', 'पैड लिंग' आदि गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ में सात आतंकवादियों की संपत्तियां कुर्क कीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/भाषा। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में पुलिस ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) भागे सात आतंकवादियों की संपत्ति बृहस्पतिवार को कुर्क कर ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इन आतंकवादियों को भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस की विशेष जांच इकाइयों (एसआईयू) की एक टीम ने किश्तवाड़ में विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी कमांडरों की संपत्तियों पर कार्रवाई संबंधी नोटिस लगा दिए। उन्होंने बताया कि ये सभी आतंकवादी पीओके से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जावेद ने सात आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क किए जाने की पुष्टि की।

न्यायाधीशों को संपत्ति का ब्यौरा देने की अनिवार्यता संबंधी कानून लाने की योजना नहीं: सरकार

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को बताया कि संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार उच्च न्यायापालिका के न्यायाधीशों को संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य बनाने संबंधी कानून लाने की उसकी कोई योजना नहीं है।

एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा की गई संपत्ति की घोषणा का ब्योरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। मंत्री से एक अन्य प्रश्न पूछा गया था, ''क्या सरकार उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य बनाने के लिए किसी कानून बनाने पर विचार कर रही है, जैसा कि संसदीय स्थायी समिति ने अगस्त, 2023 की अपनी रिपोर्ट 'न्यायिक प्रक्रियाएं और उनके

सुधार' में सिफारिश की है।'' उन्होंने इसके जवाब में कहा, ''नहीं''। उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 26 अगस्त, 2009 को न्यायाधीशों द्वारा प्रस्तुत परिसंपत्तियों के विवरण को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक करने का निर्णय लिया था। मेघवाल ने रेखांकित किया, ''इसके अलावा, पूर्ण न्यायालय ने 8 सितंबर, 2009 की अपनी बैठक में 31 अक्टूबर, 2009 को या उससे पहले परिसंपत्तियों की घोषणा को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर डालने का संकल्प लिया, और यह पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर है।''

रेलवे नेटवर्क में कुल 136 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं परिचालन में : सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि 21 नवंबर तक 136 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं बेहतर सुरक्षा और आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ चालू थीं।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, कहा कि इन सुरक्षा विशेषताओं और आधुनिक यात्री सुविधाओं में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली 'कवच', तेज गति, पूरी तरह से सीलबंद गैंगवे, स्वचालित प्लग डोर, बेहतर आरामदेह सवारी, हॉट केस के प्रावधान के साथ मिनी पेंट्री, बोतल कूलर, डीप फ्रीजर और गर्म पानी बॉयलर आदि हैं। मंत्री विभिन्न राजनीतिक दलों के नौ सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे, जो वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने के पीछे के तर्क, उनकी व्यस्तता, सुविधाएं, यात्री प्रतिक्रिया और महाराष्ट्र के साथ-साथ नई दिल्ली-काठगोदाम मार्ग पर सेवाओं के बारे में जानना चाहते थे।

वैष्णव ने कहा, ''वर्तमान में, 22 वंदे भारत सेवाएं, मूल या समाप्ति के आधार पर, महाराष्ट्र राज्य में स्थित स्टेशनों की जरूरतों को पूरा कर रही हैं।'' उन्होंने कहा, ''...दिल्ली-काठगोदाम सेक्टर में तीन जोड़ी मेल/एक्सप्रेस सेवाएं संचालित होती हैं, जिनमें 12039/40 काठगोदाम-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस भी शामिल है।'' वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत सेवाओं को मार्ग में सेक्शन की अधिकतम स्वीकार्य गति से संचालित किया जा रहा है ताकि गति क्षमता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और गति को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अजमेर मामले पर स्वत: संज्ञान लें प्रधान न्यायाधीश: पर्सनल लॉ बोर्ड

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण की मांग पर चिंता जताई और कहा कि प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना को इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय अदालत आगे ऐसे विवादों के लिए रास्ता नहीं खोलें।

अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए एक वाद स्थानीय अदालत में दायर किया गया है। अदालत ने बुधवार को वाद को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने बयान में कहा, ''पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर की विभिन्न अदालतों में मस्जिदों और दरगाहों पर दावा किए जाने पर चिंता व्यक्त करता है। इस तरह के दावे कानून और संविधान का खुला मजाक हैं।'' उनका कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के मद्देनजर इस तरह के दावों का कोई आधार नहीं बनता क्योंकि संसद द्वारा पारित इस कानून में स्पष्ट किया गया है कि 15 अगस्त, 1947 तक की किसी भी पूजा स्थल की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी

देशभर में महिलाओं के लिए एकीकृत सहायता प्रणाली लागू करने की याचिका तर्कसंगत नहीं: न्यायालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की महिला एकीकृत सहायता प्रणाली को पूरे भारत में लागू करने का निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका में उठाया गया मुद्दा तर्कसंगत नहीं है।

यह प्रणाली हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय तक निर्बाध पहुंच प्रदान करती है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर नालसा द्वारा प्रशासनिक पक्ष से विचार किया जा सकता है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस से मौखिक टिप्पणी में कहा, ''ये ऐसे मामले हैं जो तर्कसंगत नहीं हैं।'' उच्चतम न्यायालय एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नालसा महिला एकीकृत सहायता प्रणाली को लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया। याचिका में कहा गया कि पिछले तीन वर्षों से जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ में एक परियोजना का परीक्षण किया जा रहा है। पीठ ने इस मुद्दे पर प्राधिकरण की राय को रिकॉर्ड पर रखने के लिए नालसा के वकील को छह सप्ताह का समय दिया। सितंबर 2023 में मामले की सुनवाई करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने कहा, ''इस मामले में आगे बढ़ने से पहले, हम नालसा से उस योजना के बारे में रिपोर्ट चाहते हैं, जिसे याचिकाकर्ता लागू होते देखना चाहते हैं।'' अधिवक्ता सत्य मित्रा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि यह एक ''सफल परियोजना'' है और वे चाहते हैं कि इसे पूरे देश में लागू किया जाए।

याचिकाकर्ता ने कहा कि यह महिला हेल्पलाइन-181, नालसा कानूनी सहायता हेल्पलाइन-15100 और अन्य सभी सरकारी योजनाओं की प्रौद्योगिकी एकीकृत प्रणाली है, जिसका उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को आपराधिक न्याय प्रणाली तक परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान करना और उन्हें अत्याचारों से सशक्त बनाना और उनकी रक्षा करना है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा, ''यह परियोजना पिछले तीन वर्षों से जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ में परीक्षण आधार पर काम कर रही है।'' उन्होंने कहा कि नालसा महिला एकीकृत सहायता प्रणाली को देश भर में विस्तारित करने के लिए विशेष बजट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो योजनाएं इसका हिस्सा है, उन्हें पहले ही वित्त पोषित किया जा चुका है और प्रबंधन के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर भी मुफ्त में उपलब्ध है।

यूजी छात्रों को जल्द मिलेगा डिग्री पाठ्यक्रमों की अवधि घटाने या बढ़ाने का विकल्प : यूजीसी प्रमुख

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थान जल्द ही स्नातक (यूजी) छात्रों के सामने पाठ्यक्रमों की अवधि को छोटा करने या बढ़ाने का विकल्प पेश कर सकेंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस सप्ताह एक बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए त्वरित डिग्री प्रोग्राम (एडीपी) और विस्तारित डिग्री प्रोग्राम (ईडीपी) की पेशकश के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मसौदा मानदंडों को अब हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक पटल पर रखा जाएगा। कुमार ने कहा कि डिग्रियों में पाठ्यक्रमों की अवधि छोटी किए जाने या बढ़ाए का उल्लेख होगा और इन डिग्रियों को आगे की पढ़ाई या नौकरी के लिए निर्धारित अवधि की डिग्री के समान माना जाएगा। शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय भी छात्रों को निर्धारित अवधि से पहले या बाद में अपनी डिग्री पूरी करने का विकल्प देते हैं। कुमार ने कहा, ''छात्र पढ़ाई की क्षमताओं के आधार पर अपने अध्ययन की अवधि को छोटा करने या बढ़ाने के लिए इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। एडीपी के तहत छात्रों को प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करके तीन साल या चार साल का पाठ्यक्रम कम समय में पूरा करने का विकल्प मिलेगा, जबकि ईडीपी में प्रति सेमेस्टर कम क्रेडिट अर्जित करके पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाने का विकल्प मिलेगा।'' उन्होंने कहा, ''एडीपी और ईडीपी के तहत, छात्र मानक-अवधि कार्यक्रम के समान कुल क्रेडिट अर्जित करते हैं। उच्च शिक्षण संस्थान इन कार्यक्रमों के लिए छात्रों की पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए समितियां स्थापित करेंगे।''

उद्घाटन बेंगलूरु में गुरुवार को बीबीएमपी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निगम की ओर से दूसरे चरण की ठोस अपशिष्ट स्थानांतरण इकाई और स्वचालित अपशिष्ट छँटाई इकाई का उद्घाटन मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने किया। इस मौके पर मंत्री जमीर अहमद, दिनेश गुंडुराव, बीबीएमपी के आयुक्त समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे।

लोकायुक्त पुलिस ने मुडा के पूर्व आयुक्त से पूछताछ की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैसूरु। मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा-एमयूडीए) स्थल आवंटन मामले की जांच कर रही लोकायुक्त पुलिस ने बृहस्पतिवार को अपने पूर्व आयुक्त पी. एस. कांताराजू से पूछताछ की। लोकायुक्त सूत्रों ने यह जानकारी दी। कांताराजू सितंबर 2017 से नवंबर 2019 तक दो वर्ष के लिए एमयूडीए के आयुक्त थे। यहां लोकायुक्त पुलिस कार्यालय से बाहर आने के बाद एमयूडीए के पूर्व आयुक्त ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने मामले से संबंधित सभी बिंदु जांच अधिकारी (आईओ) के समक्ष प्रस्तुत किए।

कांताराजू ने कहा, 2017 में बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिन लोगों से भूखंड लिए गए थे उन्हें बराबर माप की अविकसित भूमि दी जाएगी। हमने दिसंबर 2017 में एमयूडीए बोर्ड की बैठक में इस मामले को प्रस्तुत किया। यह मुद्दा एमयूडीए के एक समेकित निर्णय से संबंधित था। आईओ ने मुझसे इस मुद्दे पर लिए गए निर्णय के बारे में पूछा, जिसे मैंने समझाया। इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या, उनकी पत्नी पार्वती बी. एम., उनके रिश्तेदार मल्लिकार्जुन स्वामी और अन्य आरोपी हैं। एमयूडीए मामले में आरोप है कि सिद्दरामय्या की पत्नी से अधिगृहित जमीन के बदले उन्हें मैसूरु के एक रिहायशी इलाके में भूखंड आवंटित किया गया था, जिसका संपत्ति मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था। एमयूडीए ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50 : 50 योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां आवासीय लेआउट' विकसित किया गया था।

विवादास्पद योजना के तहत, मुडा ने 'आवासीय लेआउट' बनाने के लिए भूमि खोने वालों को उनसे अधिगृहित अविकसित भूमि के बदले में 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की। आरोप है कि मैसूरु तालुका के कसाबा होबली के कसारे गांव के सर्वे नंबर 464 में स्थित 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी हक नहीं है। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय ने इस 'घोटाले' की जांच शुरू कर दी है।

कर्नाटक में मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की चर्चा : परमेश्वर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के गृहमंत्री जी. परमेश्वर ने बृहस्पतिवार को कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने की भी चर्चा है और इन मामलों पर फैसला पार्टी नेतृत्व को करना है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष के रूप में उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार चार साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और इस पद पर उन्हें कार्यकाल विस्तार दिया गया। परमेश्वर ने एक सवाल के जवाब में कहा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (शिवकुमार) दिल्ली गए हैं...मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री (सिद्दरामय्या) भी आज जा रहे हैं। कल कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक है। वे उसके लिए जा रहे हैं। बैठक के बाद, मुझे नहीं पता कि वे कैबिनेट फेरबदल के बारे में आलाकमान से चर्चा करेंगे या नहीं।

उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, इसके (मंत्रिमंडल फेरबदल) साथ ही हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने की भी चर्चा सुन रहे हैं। इसलिए, इन दो बातों पर, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष आलाकमान से परामर्श के बाद क्या निर्णय लेंगे, मुझे नहीं पता। सिद्दरामय्या गुरुवार शाम राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होंगे, जबकि शिवकुमार पहले से ही वहां मौजूद हैं। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) अध्यक्ष को बदलने के सवाल पर परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने इस बारे में केवल चर्चा सुनी है, लेकिन इसको लेकर निश्चित नहीं हैं कि यह किस चरण में है। वह पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उन्होंने कहा, जैसा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के बारे में

चर्चा की जा रही है, वैसे ही केपीसीसी अध्यक्ष को बदलने के बारे में भी चर्चा हो रही है। यह आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। वे मुख्यमंत्री और मौजूदा अध्यक्ष के परामर्श से निर्णय लेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल में उनका प्रभाग बदला जाएगा, परमेश्वर ने कहा कि यह आलाकमान को तय करना है। उन्होंने कहा, अब तक मैंने आलाकमान के निर्णयों का पालन किया है और पिछले 35 वर्षों से उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारियां दी हैं, उन्हें पूरा किया है। मैं ऐसा करना जारी रखने के लिए तैयार हूं।

स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने भी कहा कि पार्टी (प्रदेश) अध्यक्ष को बदलने के बारे में कुछ हलकों में चर्चा है, क्योंकि उन्हें (शिवकुमार) जिम्मेदारी संभाले हुए पांच साल से अधिक हो गए हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, शिवकुमार ने अध्यक्ष के रूप में अच्छा काम किया है और पार्टी को सत्ता में लाये हैं। वे दिन-रात काम कर रहे हैं। इस बारे में कोई दूसरी चर्चा नहीं है लेकिन उन्हें अध्यक्ष बने हुए पांच साल से अधिक हो गए हैं और उनके पास अन्य जिम्मेदारियां हैं। अगर वे पद पर बने रहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखते हैं कि वे (नेतृत्व) क्या निर्णय लेते हैं।

केपीसीसी अध्यक्ष पद के दावेदारों में से एक माने जा रहे लोकनिर्माण (पीडब्ल्यूडी) मंत्री सतीश जरकीहोली ने बुधवार को कहा कि पार्टी अध्यक्ष पद कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक कठिन काम है और इसे संभालना एक जिम्मेदारी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही मंत्रिमंडल में फेरबदल और मंत्रियों के कामकाज के मूल्यांकन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। मंत्री पद के इच्छुक विधायकों के एक वर्ग की ओर से भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। कुछ विधायकों ने तो मंत्री बनने की इच्छा खुले तौर पर जाहिर की है।

कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के महासचिव गुरप्पा नायडू के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज

बेंगलूरु। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के महासचिव गुरप्पा नायडू के खिलाफ एक शिक्षिका की शिकायत के आधार पर छेड़छाड़ और आपराधिक धमकी का एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह बेंगलूरु के एक स्कूल में कार्यरत है, जहां 75 से अधिक महिलाएं काम करती हैं। अड़तीस वर्षीय महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वह जिस स्कूल में कार्यरत है, नायडू उसके चेयरमैन हैं।

महिला ने आरोप लगाया कि यह अपराध एक मार्च, 2021 से 15 अगस्त, 2023 के बीच हुआ। इस बीच गुरप्पा नायडू ने आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। शिक्षिका की शिकायत के आधार पर चन्नम्मानकेरे अच्युकट्टे पुलिस थाने ने 26 नवंबर को गुरप्पा नायडू के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 354, 506, 509 504 के तहत एक मामला दर्ज किया। संपर्क किये जाने पर नायडू ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये झूठे और निराधार हैं। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस मुद्दे पर एक संवाददाता सम्मेलन करेंगे।

समीक्षा बैठक

बेंगलूरु में गुरुवार को जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों और नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री गृह कार्यालय 'कृष्णा' में मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या से मुलाकात की और चर्चा की। मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु चेक वितरित किया गया। समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना समेत कई प्रमुख लोग मौजूद थे।

बीईएमएल को चेन्नई मेट्रो से मिला 3,658 करोड़ रुपये का अनुबंध

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु / नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीईएमएल ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसे चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड से 3,658 करोड़ रुपये का एक अनुबंध मिला है। बीईएमएल इस अनुबंध के तहत चेन्नई मेट्रो को 210 मेट्रो कोच से लैस 70 ट्रेन सेट की आपूर्ति करेगी। इन मेट्रो ट्रेन सेट का इस्तेमाल चालक-रहित मेट्रो संचालन में किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित होने वाली बीईएमएल ने एक बयान में कहा कि ये मेट्रो ट्रेन चेन्नई में तीन प्रमुख मेट्रो गलियारों- माधवरम से सिपकोट, लाइटहाउस से पूनमल्ली और माधवरम से शोलिंगनल्लूर पर संचालित की जाएंगी। चेन्नई में कुल मेट्रो नेटवर्क 118.9 किलोमीटर तक फैला है, जिसमें 76.3 किलोमीटर का खंड एलिवेटेड है जबकि 42.6 किलोमीटर भूमिगत ट्रैक शामिल हैं। इस अनुबंध के तहत पहले ट्रेन सेट की आपूर्ति जनवरी, 2027 में की जाएगी जबकि अंतिम ट्रेन सेट अप्रैल, 2029 तक मिलने की उम्मीद है।

बीईएमएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शांतनु रॉय ने कहा, इस अनुबंध में मानक गेज मेट्रो रोलिंग स्टॉक और डिपो मशीनरी एवं संयंत्र के लिए डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, परीक्षण एवं प्रशिक्षण के साथ 15 साल का व्यापक रखरखाव भी शामिल है।

वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
Ministry of Finance
Department of Financial Services

फा. सं. 19/2/2019 पीआर — द्वितीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), नई दिल्ली में अध्यक्ष के पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), नई दिल्ली में अध्यक्ष के पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसका कार्यकाल 5 (पाँच) वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होगा।

पीएफआरडीए के अध्यक्ष का प्रतिमाह का समेकित वेतन और भत्ता, बिना आवास और कार की सुविधा 5,62,500/- रुपए होगा। पद के संबंध में विवरण और पात्रता संबंधी शर्तें मंत्रालय की वेबसाइट http://www.financialservices.gov.in और पीएफआरडीए की वेबसाइट http://www.pfrda.org.in पर दी गई हैं। पूरी तरह भरे हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30.12.2024 शाम 5.30 बजे तक है। उम्मीदवार http://rect.pfrda.org.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या योग्यता को स्पष्टतया दर्शाते हुए आवेदन नीचे दिए गए पते पर भेजे जा सकते हैं :

श्री हरकेश चन्द्र,
अवर सचिव, भारत सरकार, वित्तिय सेवाएं विभाग,
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 1, द्वितीय तल, जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001. दूरभाष सं. 011-23748760

वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
Ministry of Finance
Department of Financial Services

फा. सं. 19/2/2019 पीआर — द्वितीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), नई दिल्ली में पूर्णकालिक सदस्य (विधि) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), नई दिल्ली में पूर्णकालिक सदस्य (विधि) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसका कार्यकाल 5 (पाँच) वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होगा।

पीएफआरडीए के पूर्णकालिक सदस्य (विधि) का प्रतिमाह का समेकित वेतन और भत्ता, बिना आवास और कार की सुविधा के, 5.00 लाख रुपए होगा। पद के संबंध में विवरण और पात्रता संबंधी शर्तें मंत्रालय की वेबसाइट http://www.financialservices.gov.in और पीएफआरडीए की वेबसाइट http://www.pfrda.org.in पर दी गई हैं। पूरी तरह भरे हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30.12.2024 शाम 5.30 बजे तक है। उम्मीदवार http://rect.pfrda.org.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या योग्यता को स्पष्टतया दर्शाते हुए आवेदन नीचे दिए गए पते पर भेजे जा सकते हैं :

श्री हरकेश चन्द्र,
अवर सचिव, भारत सरकार, वित्तिय सेवाएं विभाग,
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 1, द्वितीय तल, जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001. दूरभाष सं. 011-23748760

वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
Ministry of Finance
Department of Financial Services

फा. सं. 19/2/2019 पीआर — द्वितीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), नई दिल्ली में पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), नई दिल्ली में पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसका कार्यकाल 5 (पाँच) वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होगा।

पीएफआरडीए के पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) का प्रतिमाह का समेकित वेतन और भत्ता, बिना आवास और कार की सुविधा के, 5.00 लाख रुपए होगा। पद के संबंध में विवरण और पात्रता संबंधी शर्तें मंत्रालय की वेबसाइट http://www.financialservices.gov.in और पीएफआरडीए की वेबसाइट http://www.pfrda.org.in पर दी गई हैं। पूरी तरह भरे हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30.12.2024 शाम 5.30 बजे तक है। उम्मीदवार http://rect.pfrda.org.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या योग्यता को स्पष्टतया दर्शाते हुए आवेदन नीचे दिए गए पते पर भेजे जा सकते हैं :

श्री हरकेश चन्द्र,
अवर सचिव, भारत सरकार, वित्तिय सेवाएं विभाग,
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 1, द्वितीय तल, जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001. दूरभाष सं. 011-23748760

सदानंद गौड़ा ने कर्नाटक भाजपा में गुटबाजी पर दुख जताया, केंद्रीय नेतृत्व से कदम उठाने का आग्रह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

राज्य के लोग भाजपा चाहते हैं। शिग्गांव, संदूर और चन्नपटना विधानसभा क्षेत्रों में हाल में हुए उपचुनावों में भाजपा की हार की ओर इशारा करते हुए गौड़ा ने कहा कि लोग कांग्रेस के कुशासन की चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि भाजपा में विभाजन और गुटबाजी की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा के पास अच्छे विचार और एजेंडा होने के बावजूद, हमारे पास इसे भुनाने के लिए मजबूत प्रणाली का अभाव है।

बेंगलूरु। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता डी वी सदानंद गौड़ा ने बृहस्पतिवार को अपनी पार्टी की कर्नाटक इकाई में गुटबाजी पर दुख व्यक्त किया और इसे ''अत्यंत दुखद'' करार दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री गौड़ा ने उनके पत्र लिखे जाने के बावजूद पार्टी आलाकमान द्वारा कदम उठाने में देरी पर भी अप्रसन्नता जतायी और उससे ''हस्तक्षेप करने और अनुशासनहीनता'' में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। पार्टी के भीतर गुटबाजी और इस पर आलाकमान की चुप्पी पर पूछे गए एक सवाल पर गौड़ा ने कहा, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हुए, क्योंकि चुनाव एक बड़ी चुनौती होते हैं, उन राज्यों में पार्टी के मुद्दों को बाद के लिए दरकिनार किया जाना स्वाभाविक है, जहां चुनाव नहीं हैं। इसलिए कुछ देरी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे चुप रहेंगे।

उन्होंने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, हालांकि, आपके सवाल में सच्चाई है, क्योंकि मैंने दो पत्र लिखे हैं, एक पहले और दूसरा हाल ही में, क्योंकि असंतोष पनपने लगा था। हालांकि दोनों पर कोई जवाब नहीं आया, जिससे मुझे लगा कि केंद्रीय नेतृत्व यहां के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहा है।

उन्होंने कहा, ''यह दुखद है कि कर्नाटक, जिसे दक्षिण भारत में भाजपा के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है, आज वहां कई दरवाजे हैं (भीतर के समूहों की ओर इशारा करते हुए)।'' वरिष्ठ विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल के नेतृत्व में पार्टी नेताओं का एक समूह, जिसमें भाजपा विधायक रमेश जारकीहोली भी शामिल हैं, राज्य नेतृत्व, विशेषकर अध्यक्ष विजयेंद्र येडीयुरप्पा की आलोचना कर रहा है और वक्फ भूमि मुद्दे पर पार्टी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों से दूर रहने के बाद, इसी मुद्दे पर समानांतर आंदोलन भी कर रहा है।

यतनाल और जारकीहोली ने विजयेंद्र की खुलकर आलोचना की है और उन पर सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ ''समायोजन की राजनीति'' में लिप्त होने तथा अपने पिता एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बी एस येडीयुरप्पा के साथ मिलकर पार्टी को अपने चंगुल में रखने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। गौड़ा ने याद किया कि पार्टी में पहले उन दिग्गजों के नेतृत्व वाले गुटों के बीच बहुत अधिक गुटबाजी थी, जिन्होंने राज्य में पार्टी को खड़ा किया - दिवंगत अनंत कुमार और येडीयुरप्पा। पहले भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके गौड़ा ने कहा, लेकिन तब दरार कभी सड़कों पर नहीं आयी।

उन्होंने कहा, ''कर्नाटक भाजपा के इतिहास में, यह पहली बार है कि पार्टी के भीतर की आंतरिक उलझनें सड़कों पर आई हैं। यह दुखद है। राज्य में पार्टी के तथाकथित स्वयंभू वरिष्ठ नेताओं में से कोई भी, जिसमें मैं भी शामिल हूं, इसे ठीक करने की स्थिति में नहीं है, जबकि कुछ लोग चीजों को ठीक करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें फायदा होगा, यहां पार्टी में ऐसे नेता भी हैं। इसलिए आलाकमान को हस्तक्षेप करना होगा।'' गौड़ा ने कहा कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा विपक्ष को मुद्दे दिए जाने के बावजूद, पार्टी में आंतरिक मतभेद इस पर हावी हो रहे हैं और इससे पार्टी कार्यकर्ताओं को दुख हो रहा है।

उन्होंने कहा, ''अब मेरे पास पार्टी की कोर कमेटी का हिस्सा होने के अलावा कोई और जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं उस पार्टी की स्थिति को देखकर दुखी हूं जिसने मुझे राज्य में शासन करने के लिए पद सहित सब कुछ दिया..... यह अत्यंत दुखद है।'' दिल्ली चुनाव से पहले कर्नाटक में पार्टी के मामलों पर ''गंभीरता से विचार'' करने की पार्टी नेतृत्व से अपील करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री गौड़ा ने उससे अनुशासन से समझौता न करने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि अगर विस्तृत जांच के बाद गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो पार्टी एक बार फिर एकजुट हो जाएगी।

उन्होंने कहा, राज्य के लोग भाजपा चाहते हैं।'' शिग्गांव, संदूर और चन्नपटना विधानसभा क्षेत्रों में हाल में हुए उपचुनावों में भाजपा की हार की ओर इशारा करते हुए गौड़ा ने कहा कि लोग कांग्रेस के कुशासन की चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि भाजपा में विभाजन और गुटबाजी की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा के पास अच्छे विचार और एजेंडा होने के बावजूद, हमारे पास इसे भुनाने के लिए मजबूत प्रणाली का अभाव है। उन्होंने कहा कि भाजपा की गुटबाजी की कमजोरी कांग्रेस की ताकत बन गई है।

यतनाल और टीम द्वारा विजयेंद्र को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं करने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए गौड़ा ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा की गई थी और उस निर्णय को स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर किसी को इस पर आपत्ति है, तो उन्हें नेतृत्व को बताना चाहिए और इस पर चर्चा सड़कों पर नहीं करनी चाहिए।

दक्षिण भारत में छतों पर सौर संयंत्र लगाने को बढ़ावा देने के लिए इकोफाई, स्वेलेक्ट एनर्जी में समझौता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/बेंगलूरु। हरित परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी इकोफाई ने दक्षिण भारत में सौर ऊर्जा की पहुंच को सुलभ बनाने के लिए स्वेलेक्ट सिस्टम्स लि. के साथ समझौता किया है। एवरफोर्स कैपिटल समर्थित इकोफाई ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि वह साझेदारी के तहत स्वेलेक्ट की विनिर्माण और वितरण इकाइयों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पहुंच बनाएगी और सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए वित्तीय समाधान प्रदान करेगी। कंपनी ने कहा कि यह साझेदारी रणनीतिक रूप से सरकार की पीएम सूर्य घर पहल के साथ जुड़ी हुई है। इसका उद्देश्य सुलभ ऋण समाधान प्रदान कर छत पर लगने वाले (रूफटॉप) सौर संयंत्र स्थापना में तेजी लाना है। इकोफाई की सह-संस्थापक प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राजश्री नांबियार ने कहा, स्वेलेक्ट की विनिर्माण और वितरण क्षमताओं के साथ...जुड़कर हम न केवल वित्तीय समाधान प्रदान कर रहे हैं बल्कि दक्षिण भारत में घरों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) के लिए ऊर्जा के क्षेत्र स्वावलंबन हासिल करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इस साझेदारी पर स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आर चेलप्पन ने कहा, ऊर्जा क्षेत्र में चार दशकों की विशेषज्ञता के साथ हम मानते हैं कि जब सौर ऊर्जा अपनाने की बात आती है तो कर्ज आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। इकोफाई के साथ हमारा सहयोग इस चुनौती का सीधा समाधान करता है।

कलबुर्गी जेल की मुख्य अधीक्षक को मिली धमकी

कलबुर्गी। कलबुर्गी जेल की मुख्य अधीक्षक आर. अनीता ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें ऑडियो संदेश के जरिये धमकी मिली है। हालांकि पुलिस ने कहा कि उसे इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली। अनीता ने यहां पत्रकारों से कहा, किसी ने पुलिस निरीक्षक को एक ऑडियो संदेश भेजा जिसमें कहा गया कि वे उनकी कार को उड़ा देंगे। मुझे व्यक्तिगत तौर पर अब तक ऐसा कोई संदेश नहीं मिला है, इसलिए मैं पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करा रही हूं। अनीता ने कहा कि कथित धमकी के बाद वह अब और ज्यादा सतर्कता बरत रही हैं।

अनीता ने पिछले महीने कलबुर्गी सेंट्रल जेल की मुख्य अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था। उस समय कथित तौर पर तीन कैदियों को विशेष सुविधाएं मिलने से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद में छापा मारा गया था।

मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान सम्मिट की तैयारियों का लिया जायजा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। प्रदेश में आगामी 9 से 11 दिसम्बर को आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को समिट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बस में बैठकर जयपुर शहर का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जयपुर एयरपोर्ट से आयोजन स्थल जयपुर एक्जीबिशन एंड कन्वेन्शन सेंटर (जेईसीसी) तक विभिन्न तैयारियों का अवलोकन किया तथा अधिकारियों को समिट के ऐतिहासिक आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

शर्मा ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार अपने पहले वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रही है। राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं तथा यह आयोजन राज्य की औद्योगिक दिशा को गति देने में मील का पत्थर साबित होगा। यह समिट राजस्थान को खनन, स्टोन, शिक्षा, चिकित्सा, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे लाने में महती भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आएंगे। ऐसे में राज्य सरकार तैयारियों एवं व्यवस्थाओं को पूरा करने में मिशन मोड में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि दुनिया में राजस्थान की अपनी एक पहचान है तथा प्रवासी राजस्थानियों की खासियत है कि वह अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान अपनी मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है तथा इस समिट में राज्य के आतिथ्य, संस्कृति, परम्पराओं की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिट में देश-विदेश से शामिल होने वाले निवेशकों, उद्योगपति तथा अतिथिगणों के आतिथ्य में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने एयरपोर्ट से आयोजन स्थल तक पहुंचने के विभिन्न रूट का निरीक्षण किया तथा वहां साफ-सफाई, ट्रैफिक व्यवस्था, सड़कों का सुदृढीकरण, शहर का सौन्दर्यीकरण, आवागमन संबंधी संसाधन सहित विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल जेईसीसी पहुंचकर उद्घाटन सत्र के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों, अतिथियों की बैठक व्यवस्था तथा अन्य तैयारियों के विषय में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को तैयारियों को अन्तिम रूप देने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री समिट के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के लिए जयमहल पैलेस भी पहुंचे। मुख्यमंत्री को प्रमुख शासन सचिव उद्योग एवं वाणिज्य अजिताभ शर्मा ने समिट की तैयारियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस दौरान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के. के. विश्नोई, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक गुप्ता सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

रामायण में सीता और महाभारत में गीता हमारी मार्गदर्शक : बागड़े

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने रामायण और गीता को विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ बताते हुए कहा है कि यही भारत की संस्कृति और धर्म है। बागड़े गुरुवार को अखिल भारतीय यादव महासभा अहीर द्वारा 'भगवान कृष्ण विचार एवं जनमानस' विषयक आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रामायण में सीता और महाभारत में गीता हमारी मार्गदर्शक हैं। सीता माई ने जो कठिनाई झेली वह जीवन पथ का आलोक है। उन्होंने यादव महासभा द्वारा कृष्ण के सर्वधर्म सद्भाव की संस्कृति का सर्वत्र प्रसार करने का आह्वान किया। उन्होंने कृष्ण के फल की इच्छा के बगैर कर्म करने के गीता के संदेश से प्रेरणा लेकर जीवन जीने पर जोर दिया।

राज्यपाल ने कहा कि भगवान कृष्ण कभी इतिहास नहीं हो सकते। वह जनमानस में गहरे से रचे-बसे हैं। कृष्ण की बांसुरी और राधा से उसकी डाह की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने भगवान कृष्ण को युगप्रवर्तक बताते हुए कहा कि जहां अन्याय-अत्याचार हुआ उसका विरोध किया। संस्कृति की हानि हुई तो भगवान ने आगे आकर उसका संरक्षण किया।

उन्होंने कृष्ण- सुदामा की मित्रता की चर्चा करते हुए कहा कि उनकी मित्रता निभाने के संस्कार से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने माखनचोर के उनके स्वरूप की कथा सुनाते हुए कहा कि वह इसलिए आकर्षित करते हैं कि हमेशा ईश्वर होते हुए भी मनुष्य की भांति रहे। समारोह में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कृष्ण और यादव समाज से जुड़े गौरव की चर्चा की। अखिल भारतीय यादव महासभा के डा. अशोक यादव ब्रिगेडियर प्रताप सिंह आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

देवासी ने किया कंबल वितरण अभियान का शुभारंभ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मानव आकांक्षा अधिकार अभियान ट्रस्ट के द्वारा सर्दी से बचाव के लिए सिरोही जिले के राजकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को 5500 कंबल वितरण अभियान का शुभारम्भ बुधवार को सिरोही नगर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टांकरिया से किया गया। मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्यमंत्री ओटाराम देवासी के कर कमलों से इस अभियान की शुरुआत की गई। मंत्री ने मानव आकांक्षा अधिकार अभियान ट्रस्ट के अध्यक्ष जगदीश पुरोहित को इस पुनीत कार्य के लिए साधुवाद दिया एवं बताया कि ऐसे सेवा और परोपकार की भावना सभी को रखनी चाहिए एवं सदैव सभी के सहयोग के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस दौरान अतिथियों के हाथ से कार्यक्रम में विराजमान सभी छात्र-छात्राओं को कंबल वितरित किए गए और कंबल वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने की उन्होंने अपने संबोधन में अपने ट्रस्ट के माध्यम से जगदीश पुरोहित द्वारा की जा रही सेवा की तारीफ करते हुए उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को आगे बढ़ने और सेवा कार्य करते रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम में आयोजकों ने बताया कि इस अभियान के तहत 50 गांवों की 60 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार 5500 कंबल वितरित किये जाएंगे। उन्होने बताया कि ट्रस्ट के माध्यम से वे विभिन्न सेवा उपयोगी अभियान चलाते हैं और जरूरतमंदों के लिए घर जाकर सेवा योजना चलाते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिरोही के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मंच संचालन राकेश पुरोहित ने किया।

उपचुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे इसका मंथन करेंगे : पायलट

जयपुर/दक्षिण भारत। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि राज्य की सात सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे, इसका मंथन करेंगे। पायलट ने दौसा से कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव जीते दीनदयाल बैरवा के साथ आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, यह बात सही है कि उपचुनावों में जो परिणाम पूरे प्रदेश में आये वो हमारे पक्ष में नहीं रहे उसका भी मंथन करेंगे कि आगे क्या करना है। दौसा निर्वाचन क्षेत्र से जो पार्टी की जीत हुई उसका श्रेय दौसा की जनता को जाता है। पायलट ने कहा, दौसा विधानसभा क्षेत्र के लिये जो भी संघर्ष करना होगा वो हम सब मिलकर करेंगे। इस क्षेत्र ने दशकों तक हम सब का सहयोग किया..पार्टी का गढ़ रहा और सब लोगों ने वास्तव में साबित किया है कि देश में जो नाम दौसा का है और कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं।

उन्होंने कहा कि चुनाव के समय अगर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सब एकजुट नहीं रहते तो यह चुनाव इतना आसान नहीं था। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने प्रदेश में उपचुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस नेता ने कहा, भाजपा ने पूरी पार्टी, पूरा संगठन, पूरी सरकार, मंत्री, पूरा तंत्र सब लगाया लेकिन कांग्रेस पार्टी को दौसा उपचुनाव में जीत मिली और इस उपचुनाव परिणाम से आने वाले समय में हम सब लोगों को ताकत मिलेगी।

लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनजन तक पहुंचाने में महती भूमिका निभाएं अधिकारी : मीणा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि प्रदेश में हर तबके तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार अति संवेदनशील होकर कार्य कर रही है।

उन्होंने प्रशासनिक वर्ग का आह्वान किया कि वह लोक हितैषी निर्णय एवं कार्यक्रमों को जनजन तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका अदा करें। वे गुरुवार को अजमेर के आरआरटीआई सभागार में आरटीएस के 31वें बैच के तहत आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आरटीएस प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी वर्ग अपने कार्य क्षेत्र में संवेदनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि वे सदैव गरीबों को गणेश मानकर कार्य करेंगे तो उन्हें हर क्षेत्र में सफलता अर्जित होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार की सेवाओं का लाभ त्वरित एवं पारदर्शी ढंग से आम जनता पहुंचाने के उद्देश्य से ई फाइल सिस्टम को प्रभावी बनाया गया है। आम जन के अभाव अभियोगों के निराकरण के लिए सरकार हर संभव राहतकारी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कृषक वर्ग की समस्याओं के त्वरित निराकरण के भी प्रयास किया जा रहे हैं। कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने के लिए लोक जागरूकता के भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में राजस्व मंडल अध्यक्ष हेमंत कुमार गेरा ने प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण उपरांत बेहतरीन लोकसेवाएं प्रदान करने के लिए शुभकामनाएं दी। निबंधक महावीर प्रसाद ने प्रशिक्षण की बारीकियों एवं बेहतरीन अनुभवों का लाभ भावी कार्य क्षेत्र में जन-जन तक पहुंचाने की बात कही। कार्यक्रम का संयोजन गिरिराज सिंह राणावत ने किया जबकि आरआरटीआई की कार्यवाहक निदेशक कोमल चौधरी ने आभार जताया।

प्रदेश सरकार शैक्षणिक उन्नयन एवं अवसंरचना विकास के कृत संकल्प : पटेल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। संसदीय कार्य,विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत गंगाणा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मध्य पूर्व पुलिस चौकी में गुरुवार को 19.86 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित कक्षाकक्ष का विधिवत रूप से फीता काटकर लोकार्पण किया। संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने कहा माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शैक्षणिक उन्नयन एवं विद्यालयों में अवसंरचना विकास के कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कक्षा-कक्ष, लैब, पुस्तकालय एवं शौचालय निर्माण के लिए इस बजट में 350 करोड़ रुपए और प्रदेश के 750 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

पटेल ने कहा बजट में राज्य में सभी वर्गों के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्र-छात्राओं को देय मैस भत्ता 2 हजार 500 रुपए से बढ़ाकर 3 हजार रुपए प्रतिमाह किया गया है। उन्होंने कहा राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 8 वीं,10 वीं एवं 12 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य तथा जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को तीन वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ टैबलेटस निःशुल्क दिए जा रहे है।

पटेल ने कहा विद्यालय भारत के भविष्य निर्माण के केंद्र है। उन्होंने कहा शिक्षक राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्ती भूमिका निभाते है। संसदीय कार्य मंत्री ने विद्यालय में कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए 11 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा क्षेत्र के विद्यालयों के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी।

पटेल ने कहा लूणी क्षेत्र में 3 अरब रुपए से भी अधिक राशि के सड़क निर्माण के कार्य स्वीकृत हो चुके है। सभी कार्यों को तय समयावधि में पूर्ण करवा कर क्षेत्र के सड़क तंत्र का सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा क्षेत्र में निवासरत पाक विस्थापित बंधुओं की कॉलोनियों का सर्वे कर आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी।

स्वास्थ्य कार्मिकों एवं रोगियों से संवाद कर जांची स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार सुदृढ़ बनाया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग निरंतर तकनीकी नवाचार कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कर रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने अभिनव पहल करते हुए चिकित्सा संस्थानों में वीडियो कॉल के माध्यम से सीधा औचक संवाद प्रारंभ किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने इस नवाचार की शुरूआत बालोतरा जिले के जसोल क्षेत्र के आयुष्मान आरोग्य मंदिर मूंगड़ा में वीडियो कॉल कर की। उन्होंने अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक, बारां जिले के अटरू, चूरू जिले के सरदार शहर, डीग जिले के नगर एवं ब्यावर जिले के जैतारण ब्लॉक के चिकित्सा संस्थानों में वीडियो कॉल कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया।

श्रीमती राठौड़ ने चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संवाद कर उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशानिर्देश दिए। साथ ही, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस होने के कारण इस अवसर पर उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के बारे में भी चर्चा की। श्रीमती राठौड़ ने लाभार्थियों से संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं उपलब्धता के संबंध में फीडबैक भी लिया।

आएमएससीएल की प्रबंध निदेशक श्रीमती नेहा गिरि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक श्रीमती भारती दीक्षित, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्यारेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रियंका गोस्वामी, निदेशक आईईसी शाहीन अली खान, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों सहित राज्य, संभाग एवं जिला स्तर के 100 से अधिक अधिकारियों ने दो घंटे में एक हजार से अधिक कॉल कर करीब 1 हजार चिकित्सा संस्थानों में सीधा संवाद किया।

खादिमों ने अजमेर दरगाह के खिलाफ दायर याचिका को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की चाल बताया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। अजमेर दरगाह के खादिमों (सेवकों) का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि 'दक्षिणपंथी ताकतें' मुसलमानों को अलग-थलग करने और देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए एक वाद स्थानीय अदालत में दायर किया गया है। अदालत ने बुधवार को वाद को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), दिल्ली को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दरगाह कमेटी के पदाधिकारियों ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि अजमेर दरगाह के खादिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था 'अंजुमन सैयद जादगान' के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि संस्था को मामले में पक्षकार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दरगाह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन आती है और एएसआई का इस जगह से कोई लेना-देना नहीं है।

सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि उक्त याचिका समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के लिए जानबूझकर की जा रही कोशिश है। उन्होंने कहा, समाज ने बाबरी मस्जिद मामले में फैसले को स्वीकार कर लिया और हमें विश्वास था कि उसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी चीजें बार-बार हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के संभल का उदाहरण हमारे सामने है। यह रोका जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने संभल में स्थित जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था क्योंकि दावा किया गया था कि इस जगह पर पहले हरिहर मंदिर था।

सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि वह दरगाह से जुड़े मौजूदा मामले में कानूनी राय ले रहे हैं। उन्होंने कहा, अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की पवित्र दरगाह दुनिया भर, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों और हिंदुओं में पूजनीय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दक्षिणपंथी ताकतें सूफी दरगाह को मुद्दा बनाकर मुसलमानों को अलग-थलग करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का लक्ष्य बना रही हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी कहा जाता है। सैयद सरवर चिश्ती ने कहा, यह याचिका मुसलमानों के खिलाफ काम करने वाले उस बड़े 'तंत्र' का हिस्सा लगती है जो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। यह दरगाह धर्मनिरपेक्षता का शानदार उदाहरण है, जहां न केवल मुसलमान बल्कि हिंदू भी आते हैं। यह दुनिया भर में रहने वाले लोगों की आस्था का स्थान है। उन्होंने कहा कि दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है तथा यह विविधता में एकता को बढ़ावा देती है।

सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि मस्जिदों में शिवलिंग और मंदिर तलाशे जा रहे हैं...लेकिन ये चीजें देश के हित में नहीं हैं। 'यूनाइटेड मुस्लिम फोरम राजस्थान' (यूएमएफआर) के अध्यक्ष मुजफ्फर भारती ने कहा कि यह याचिका उपासना स्थल अधिनियम 1991 का सरासर उल्लंघन है। भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से सालाना उर्स के दौरान दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेजी जाती है और इस परंपरा की शुरुआत जवाहर लाल नेहरू ने की थी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उच्चतम न्यायालय को ऐसे कृत्यों का संज्ञान लेना चाहिए, जिनसे देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। स्थानीय अदालत में याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल की गई है जिन्होंने अपने दावे के समर्थन में हर बिलास शारदा की एक किताब का हवाला देते हुए दावा किया है कि 'जहां दरगाह बनाई गई वहां एक शिव मंदिर था।' उन्होंने दावा किया, इसके अलावा, कई अन्य तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहां एक शिव मंदिर था। याचिका में गुप्ता ने दरगाह को शिव मंदिर घोषित करने, दरगाह संचालन से जुड़े अधिनियम को रद्द करने, पूजा करने का अधिकार देने और एएसआई को उस स्थान का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

चित्रकूट के भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध : आदित्यनाथ

चित्रकूट/लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि चित्रकूट धाम को उसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान दिलाने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है और इस पवित्र धाम के आध्यात्मिक के साथ-साथ भौतिक विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने चित्रकूट के अपने एक दिवसीय दौरे पर जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की जिसके बाद वह श्री महाराजाधिराज मतगजेंद्र नाथ शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री इसके बाद रामघाट पहुंचे, जहां उन्होंने मां मंदाकिनी के तट पर खड़े होकर इस पवित्र नदी की आरती उतारी और प्रदेश वासियों के सुख-समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री मां मंदाकिनी की पांच अर्चकों द्वारा होने वाली दैनिक आरती में भी शामिल हुए। आदित्यनाथ ने कहा कि जहां कभी भगवान श्रीराम ने संत तुलसीदास जी को दर्शन दिया था, आज उस पवित्र स्थल का दर्शन और पूजन करना सौभाग्य का विषय है तथा सरकार चित्रकूट के भौतिक विकास और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

हिंदू संगठन ने बांग्लादेश उप उच्चायुक्त कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला

कोलकाता/भाषा। बंगीय हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त कार्यालय तक एक रैली निकाली और पड़ोसी देश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों और आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का विरोध किया। सियालदह स्टेशन से बांग्लादेश उप उच्चायोग तक मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दक्षिण कोलकाता के बेकबागान स्थित उप उच्चायोग कार्यालय के पास पहुंचने से रोकने के लिए अवरोधक लगा दिए।

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वे 17 करोड़ की आबादी का केवल 8 प्रतिशत हैं। हिंदुओं को यहां पांच अगस्त को शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से 50 से अधिक जिलों में 200 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा है। हिंदू आध्यात्मिक नेता दास को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया जिसके बाद राजधानी ढाका और चटगांव सहित विभिन्न स्थानों पर समुदाय के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

एनओडीसी विवाद में सरकार सुंदरगढ़ के लोगों की भावनाओं का सम्मान करती है : माझी

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार प्रस्तावित 'नोर्थ ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल' में खनिज समृद्ध सुंदरगढ़ जिले को शामिल करने के प्रस्ताव के सिलसिले में जिले के लोगों की इच्छा के विरुद्ध कोई फैसला नहीं करेगी। इससे पहले सुंदरगढ़ जिले के अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य के पश्चिम हिस्से के इस जिले को एनओडीसी में शामिल किया जाएगा। सुंदरगढ़ के विधायक जोगेश सिंह द्वारा विधानसभा में इस मुद्दे को उठाये जाने के कुछ घंटे बाद माझी ने 'एक्स' पर यह (नई) घोषणा की। भद्रक जिले से विपक्षी बीजद के विधायक ब्यामकेश रे ने भी कहा कि पश्चिमी और उत्तरी ओडिशा के बीच संस्कृति, भाषा एवं परंपरा का फर्क है।

झारखंड : सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका को शिक्षक ने कक्षा के अंदर गोली मारी

देवघर (झारखंड)/भाषा। झारखंड के देवघर जिले में बृहस्पतिवार को एक सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका को एक शिक्षक ने कक्षा के अंदर छात्रों के सामने गोली मार दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना मोहनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक उन्नत माध्यमिक विद्यालय में हुई। देवघर के पुलिस अधीक्षक अंबर लाकड़ा ने बताया कि चांदनी कुमारी के हाथ में गोली लगी है। चिकित्सकों ने बताया कि देवघर सदर अस्पताल में पीड़िता का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है।

योगी आदित्यनाथ ने किया बांदा में रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बांदा (उप्र)/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को रानी दुर्गावती राजकीय मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया।

गोंडवाना की मध्यकालीन युग की रानी दुर्गावती को मुगल आक्रांताओं से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए जाना जाता है।

भारतीय इतिहास में रानी दुर्गावती की सराहना करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि यह प्रतिमा उनकी वीरता और बलिदान का प्रतीक है और भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने बांदा में विकास की परियोजनाओं में तेजी लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि विकास की सभी परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ पूरी की जाएं।

मुख्यमंत्री तेलंगाना राज्य में भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी के पुश्तैनी घर भी गए जहां उन्होंने चंद्रशेखर की दिवंगत मां को श्रद्धांजलि अर्पित की।

शीतकालीन गणना के दौरान ओडिशा के जंगलों में 2,103 हाथियों की गिनती हुयी

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा के जंगलों में 14 से 16 नवंबर तक तीन दिवसीय शीतकालीन गणना के दौरान कुल 2,103 हाथी गिने गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वन विभाग द्वारा बृहस्पतिवार को जारी गणना रिपोर्ट के अनुसार 48 वन प्रभागों में से 38 में हाथी देखे गए। इसके पहले मई महीने में हाथियों की गणना की गई थी, जिसमें 2098 हाथी गिने गए थे।

शीतकालीन गणना के दौरान जंगली हाथियों की सबसे अधिक संख्या ढेंकनाल (291) में दर्ज की गई जिसके बाद क्योंझर (160), अथगढ़ (124), देवगढ़ (123) और अंगुल (117) में दर्ज की गई। राउरकेला, क्योंझर, संबलपुर, अथमल्लिक, घुमसूर उत्तर, कालाहांडी उत्तर, कालाहांडी दक्षिण, बोलांगीर और रायराखोल जैसे प्रभागों में भी हाथियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। वहीं सिमिलिपाल उत्तर वन्यजीव अभयारण्य, सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य, बामरा वन्यजीव अभयारण्य और रायगढ़ जैसे क्षेत्रों में हाथियों की संख्या में कमी देखी गई।

रिपोर्ट के अनुसार ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन गणना अवधि के बीच 48 हाथियों की मृत्यु दर्ज की गई।

भारत के लिए 'चीन प्लस वन' से पैदा हो रहा अवसर : अरविंद सुब्रमण्यन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा कि विदेशी कंपनियों की 'चीन प्लस वन' रणनीति से भारत के लिए अवसर पैदा हो रहा है और तमिलनाडु इस विदेशी निवेश को अपने यहां लाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है।

सुब्रमण्यन ने 'सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस' की तरफ से यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि चीन, ताइवान और वियतनाम की तरह भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से घरेलू कंपनियां वैश्विक मूल्य शृंखला के साथ एकीकृत नहीं हो पाई हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक मूल्य शृंखला का हिस्सा नहीं होने से भारत के निर्यात और श्रम-सघन क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

सुब्रमण्यन ने कहा कि विदेशी कंपनियों के चीन से इतर अन्य देशों में भी विनिर्माण इकाइयां लगाने पर जोर देने की 'चीन प्लस वन' नीति से भारत के लिए अवसर पैदा हो रहा है।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु इस एफडीआई को आकर्षित करने में अपने प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने हाल ही में कहा था कि राज्य ने पिछले तीन वर्षों में नौ लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया है और 31 लाख नए रोजगार सृजित किए हैं।

इस समय पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में सीनियर फेलो के रूप में कार्यरत सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत का विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन सख्त श्रम कानूनों और कंपनियों के छोटे आकार जैसे कारणों से खराब रहा है।

इस कार्यक्रम में योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा, हम इस समय कई गंभीरता से काम कर रहे उद्यमियों को कलंकित करने के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं।

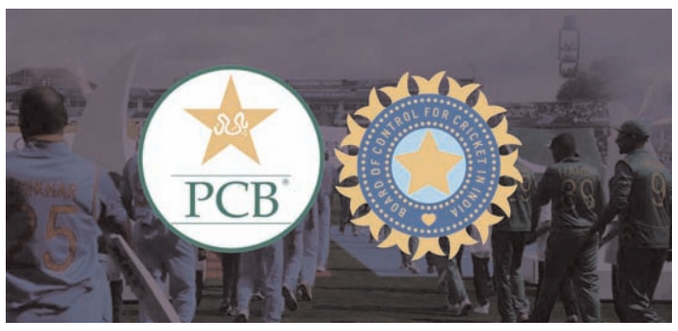

पीसीबी ने बोर्ड बैठक से पहले आईसीसी से कहा, चैंपियंस ट्रॉफी का 'हाइब्रिड मॉडल' स्वीकार्य नहीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कराची/भाषा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बृहस्पतिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को सूचित किया कि वह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 'हाइब्रिड मॉडल' स्वीकार नहीं करेगा। पीसीबी ने साथ ही विश्व संचालन संस्था से शुक्रवार को होने वाली बोर्ड बैठक में विकल्प पर चर्चा नहीं करने के लिए कहा है।

भारत के पाकिस्तान में टूर्नामेंट में खेलने के लिए अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया है जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम संबंधित उलझन सुलझान के लिए आईसीसी ने कार्यकारी सदस्यों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। एक सूत्र ने पीटीआई से कहा, ''मैं पुष्टि कर सकता हूं कि पीसीबी ने कुछ घंटे पहले आईसीसी को बताया है कि टूर्नामेंट का 'हाइब्रिड मॉडल' स्वीकार्य नहीं है।'' पीसीबी 'हाइब्रिड मॉडल' का विरोध कर रहा है और उसने आईसीसी को सलाह दी है कि चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित करने के लिए कोई अन्य विकल्प ढूंढा जाये। पाकिस्तान बोर्ड का मानना है कि 'हाइब्रिड मॉडल' में खेलने का मतलब भारत को तरजीह देना होगा। सूत्र ने कहा, ''मैं पुष्टि कर सकता हूं कि शुरू में भारतीय टीम अगर पाकिस्तान में नहीं खेल सकती थी तो पीसीबी ने इस हालत में 'हाइब्रिड मॉडल' में खेलने की संभावना पर विचार किया था। लेकिन भविष्य में 2031 तक (भारत और बांग्लादेश में वनडे विश्व कप) भारत में होने वाले सभी आईसीसी टूर्नामेंट 'हाइब्रिड मॉडल' में ही खेले जायेंगे क्योंकि पाकिस्तान भारत में नहीं खेलेगा।''

एक अन्य सूत्र ने पुष्टि की कि पीसीबी ने आईसीसी को यह भी सूचित करने के लिए याद दिलाया है कि क्या बीसीसीआई ने अपनी सरकार से लिखित में पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि भारतीय टीम को पाकिस्तान में खेलने की मंजूरी नहीं दी गई थी। सूत्र ने कहा, ''आईसीसी के नियमों के तहत अगर कोई टीम कहती है कि उसकी सरकार किसी भी आधार पर उसे दूसरे देश में खेलने की अनुमति नहीं दे रही है तो बोर्ड को अपनी सरकार के निर्देश लिखित में जमा करने होंगे जो हमने अभी तक नहीं देखे हैं।'' उन्होंने कहा कि पीसीबी ने आईसीसी के आय सृजन में बीसीसीआई और भारतीय बाजार के योगदान को स्वीकार किया है लेकिन आईसीसी को याद दिलाया कि पिछले कुछ वैश्विक टूर्नामेंट के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ अपने मैचों से राजस्व सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आईसीसी ने अभी तक वर्चुअल बैठक के समय की पुष्टि नहीं की है।

बंगाल सरकार 'स्वास्थ्य साथी' योजना के तहत खर्च में वृद्धि की जांच कर रही है : ममता

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान राज्यभर में 'स्वास्थ्य साथी' योजना के तहत खर्च में बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद सरकार को मामले की जांच करानी पड़ी।

बनर्जी ने विधानसभा में कहा, ''उस समय (आरजी कर अस्पताल की घटना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान) 'स्वास्थ्य साथी' योजना के तहत खर्च में भारी वृद्धि हुई थी। हम जांच कर रहे हैं। दोषियों को सजा दी जाएगी।''

एक सर्वेक्षण से पता चला है कि पीड़ित महिला चिकित्सक के लिए न्याय की मांग को लेकर कनिष्ठ चिकित्सकों के प्रदर्शन के दौरान निजी अस्पतालों में 'स्वास्थ्य साथी' योजना के तहत मरीजों के इलाज पर राज्य के खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।

'स्वास्थ्य साथी' योजना राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत प्रति परिवार को चिकित्सा देखभाल के लिए प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिलती है।

मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले में हजारों लोगों ने अफस्पा के खिलाफ रैली निकाली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इंफाल/भाषा। मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले में बृहस्पतिवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए रैली निकाली और राज्य से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) हटाने तथा जिरीबाम जिले में तीन महिलाओं और तीन बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की।

रैली लामलाई निर्वाचन क्षेत्र के नोनगाडा से शुरू हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए 4.5 किलोमीटर की दूरी तय की और योरबंग की ओर मार्च किया।

एक महिला प्रदर्शनकारी वाई लीमा ने कहा, रैली का आयोजन मीरा पैबिस और लामलाई निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय क्लब द्वारा किया गया था। हमने बार-बार दोहराया है कि अफस्पा उत्पीड़न का एक साधन है। इंफाल घाटी और नगा क्षेत्रों के लोगों को अफस्पा के तहत सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ा है, लेकिन सरकार ने कभी भी उनकी पीड़ा को स्वीकार नहीं किया।

इस बीच जिरीबाम जिले में कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ मणिपुर इंटीग्रीटी (सीओसीओएमआई) की छात्र शाखा के स्वयंसेवकों ने कुकी-जो उग्रवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने और अफस्पा हटाने की मांग को लेकर दो दिवसीय अभियान के तहत कई सरकारी कार्यालयों में ताले लगा दिए। स्वयंसेवकों ने सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय खाली करने पर मजबूर कर दिया तथा मुख्य दरवाजे बंद कर दिए। केंद्र ने हाल में मणिपुर के छह पुलिस थाना क्षेत्रों में अफस्पा को फिर से लागू कर दिया है जिसमें हिंसा प्रभावित जिरीबाम भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि यह निर्णय वहां जारी जातीय हिंसा के कारण लगातार अस्थिर स्थिति को देखते हुए लिया गया है।

ओडिशा में 53,480 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण : मंत्री

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बृहस्पतिवार को विधानसभा को बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में 53,480 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। बीजू जनता दल (बीजद) विधायक अरुण कुमार साहू के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा, ओडिशा भूमि अतिक्रमण निवारण (ओपीएलई) अधिनियम, 1972 के अनुसार, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाना एक सतत प्रक्रिया है।

पुजारी ने बताया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जुलाई और सितंबर माह में सभी 30 जिलों के जिलाधिकारियों को सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए थे।

पुजारी ने अपने जवाब में कहा, विभिन्न जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1,08,773 एकड़ अतिक्रमित सरकारी भूमि में से 55,293 एकड़ भूमि को मुक्त करा दिया गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि 53,480 एकड़ सरकारी भूमि पर अब भी अतिक्रमण है।

जनता की सशक्त आवाज बनेंगी प्रियंका : खरगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने प्रियंका गांधी वाद्रा के लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेने के बाद उन्हें शुभकामनाएं दीं तथा उम्मीद जताई कि वह सदन में जनता की सशक्त आवाज बनेंगी।

केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुईं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बृहस्पतिवार को निचले सदन की सदस्यता की शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने कहा कि जनता के जरूरी मुद्दों को उठाना, देश और पार्टी के लिए काम करना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी तथा वह संविधान के उसूलों के लिए लड़ाई लड़ेंगी। उनकी शपथ के बाद सोनिया गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें प्रियंका गांधी पर गर्व है। खरगे ने प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर साझा करते हुए 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''मुझे पूरा विश्वास है कि प्रियंका गांधी संसद में देश के लोगों की, ख़ासकर महिलाओं की सशक्त आवाज बनेंगी। उनका कुशल नेतृत्व, करुणा, साहस, शालीनता और दृढ़ संकल्प तथा संविधान के सिद्धांतों के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता देश की जनता को लाभ पहुंचाएगी।''

राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोस्ट में कहा, ''बहुत खुशी, बहुत गर्व, वायनाड की नई सांसद, मेरी बहन प्रियंका।'' प्रियंका गांधी के प्रति रॉबर्ट वाद्रा ने कहा, ''हम बहुत खुश हैं।'' कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और पार्टी के कई नेताओं ने प्रियंका गांधी को शुभकामनाएं दीं।

अपहरण के 31 साल बाद परिवार से मिला युवक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अपहरण के 31 साल बाद अपने परिवार से मिला युवक

गाजियाबाद (उप्र)/भाषा। गाजियाबाद जिले में वर्ष 1993 में अगवा किया गया सात साल का राजू 31 साल बाद अपने परिवार से मिला। फिरौती की रकम देने में असमर्थ होने पर उसके परिवार ने उसे मजबूरन भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था मगर तीन दशक के बाद उसे सही-सलामत अपने बीच पाकर परिवार बेहद खुश है।

दिल्ली बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए तुला राम के लिए अपने बेटे राजू से 31 साल बाद पुनर्मिलन बेहद खुशी का क्षण था।

साहिबाबाद क्षेत्र के रहने वाले तुला राम ने बृहस्पतिवार को बताया कि उनके बेटे राजू का सितंबर 1993 को साहिबाबाद के दीनबंधु पब्लिक स्कूल से घर लौटते समय अपहरण कर लिया गया था। एक टेंपो में सवार तीन लोगों ने उसे अगवा किया था। उस वक्त राजू की उम्र सात साल थी। उन्होंने बताया कि मामले में साहिबाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। काफी खोजबीन के बाद भी पुलिस राजू को बरामद नहीं कर पाई। इसी दौरान उन्हें एक पत्र मिला था जिसमें राजू को छोड़ने के एवज में आठ लाख रुपए की फिरौती मांगी गयी थी। रकम दे पाने में असमर्थ होने पर तुला राम ने मामले को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया और जांच ठंडे बस्ते में चली गई।

तुला राम ने कहा, ''इस दौरान हम इस बात को लेकर अनिश्चितता में रहे कि हमारा बेटा जीवित है भी या नहीं, लेकिन 27 नवंबर को हमारे लिए मायूसी बहुत बड़ी खुशी में बदल गयी। राजू हमारे पास वापस आ गया। वह अब 38 साल का हो चुका है।'' उन्होंने कहा, ''शुरुआत में मुझे यह मानने में हिचकिचाहट हुई कि क्या वह वाकई हमारा राजू ही है। मैं उसे घर ले गया और मां-बहनों ने उसकी छाती पर तिल और खोपड़ी में गड्ढे से उसकी पहचान की। आखिरकार 31 साल बाद हमारा खोया हुआ राजू हमें वापस मिल गया।''

पढ़ाई से बचने के लिए हॉकी को चुना था लेकिन इसने करियर बना दिया: भारतीय खिलाड़ी अभिषेक

नई दिल्ली/भाषा। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता फारवर्ड अभिषेक ने पढ़ाई से बचने के लिए हॉकी खेलना शुरू किया था लेकिन उन्हें इस फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ क्योंकि इस खेल ने उन्हें पहचान, 'स्टारडम' और वह सब कुछ दिया जो वह जिंदगी में पाना चाहते थे। अभिषेक ने हालांकि पत्राचार के माध्यम से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन इस खिलाड़ी को पता था कि हमेशा से पता था कि खेल से उन्हें बेहतर उद्देश्य मिलेगा।

पेरिस ओलंपिक में भारत के कांस्य पदक जीतने के अभियान में अहम योगदान निभाने वाले अभिषेक ने कहा, ''मैंने 11 या 12 साल की उम्र में हॉकी खेलना शुरू किया था। सोनीपत में इसके अलावा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था।'' उन्होंने कहा, '' मेरा एक दोस्त हॉकी खेलने के लिए काफी यात्रा करता था। जब मैंने देखा कि मेरे दोस्त को हॉकी में व्यस्त होने के कारण स्कूल कम आना होता है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं भी हॉकी खेलना शुरू कर दूं तो मैं भी ऐसा ही कर सकता हूं।''

भारत अगले 10 वर्षों में फीफा रैंकिंग में शीर्ष 50 में पहुंच सकता है : मांडविया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश की टीम फीफा रैंकिंग में शीर्ष 50 में पहुंच सकती है। एआईएफएफ के अध्यक्ष कल्याण चौबे सहित शीर्ष अधिकारियों ने मांडविया से मुलाकात कर उन्हें ओडिशा में मौजूदा एआईएफएफ-फीफा अकादमी और विभिन्न क्षेत्रों में चार अतिरिक्त एसी सुविधाएं बनाने की योजना के बारे में जानकारी दी। एआईएफएफ की विज्ञप्ति में मांडविया के हवाले से कहा गया, ''एक विस्तृत योजना तैयार की जानी चाहिए और उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए ताकि भारत अगले 10 वर्षों में फीफा रैंकिंग में 50 के अंदर पहुंच सकें।'' इसमें उन्होंने कहा, ''भारत में वैश्विक स्तर पर युवा प्रतिभाओं का सबसे बड़ा पूल है। ध्यान जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान पर होना चाहिए। उन्हें कोच विकास के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए जो खेल विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा।'' फीफा रैंकिंग 1992 में शुरू हुई और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 94 रही है जो उसने फरवरी 1996 में हासिल की थी। टीम कम मौकों पर शीर्ष 100 में पहुंच पाई है।

खेलो इंडिया के तहत 300 से अधिक नई खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई : मंडाविया

नई दिल्ली/भाषा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को एक लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि खेलो इंडिया योजना के तहत 3073.97 करोड़ रुपए की लागत वाली 323 नई खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम 2016-17 में देश भर में खेलों में व्यापक भागीदारी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना को 1756 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय पर 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए मंजूरी दी गयी।

सुविचार

यूं ना छोड़ ज़िंदगी की किताब को खुला, बेवक्त की हवा ना जाने कौन सा पन्ना पलट दें।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ईवीएम पर संदेह क्यों?

मतपत्रों के जरिए मतदान की पुरानी व्यवस्था बहाल करने के आग्रह को लेकर दायर की गई एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी – '... जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती। जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ हो जाती है।' – के बाद अब ऐसी बेबुनियाद मांगों पर विराम लग जाना चाहिए। ईवीएम के नतीजों पर संदेह जताकर वापस पिछली सदी के तौर-तरीकों के अनुसार चुनाव कराने की मांग उस वक्त तेज हो जाती है, जब चुनाव नतीजे आते हैं। अगर चुनाव जीत गए तो यह नेताओं का करिश्मा है, अगर हार गए तो ईवीएम में गड़बड़ है ... नेताओं और उनके राजनीतिक दलों का प्रदर्शन बेमिसाल है, बस ईवीएम आड़े आ गई, अन्यथा छप्परफाड़ वोट बरसते!' हारने के बाद ईवीएम को दोष देने वाले नेताओं को चाहिए कि वे अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करें, अपने संगठन की खामियां सुधारें। जनता ने आपको क्यों नहीं स्वीकारा, इसका पता लगाएं। हर चुनावी शिकस्त के बाद ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा देने से काम नहीं चलेगा। अगर आरोपों के अनुसार, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में ईवीएम खराब थीं तो झारखंड में सही कैसे हो गईं? ईवीएम हरियाणा में खराब थीं तो जम्मू-कश्मीर में ठीक कैसे हो गईं? ईवीएम ने राजस्थान में धोखा दे दिया तो तेलंगाना में साथ कैसे निभा दिया? जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझान आ रहे थे तो एक वरिष्ठ नेता को इसमें 'बड़ी साजिश' और 'कुछ गड़बड़' नजर आने लगी थीं! वे यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार जीत सकते हैं। उनका तर्क था कि महाराष्ट्र की जनता सत्ता पक्ष से नाराज थी, लिहाजा चुनाव में विजयश्री का वरदान विपक्ष को मिलना चाहिए था।

प्राय: वरिष्ठ नेतागण अपने समर्थकों से घिरे रहते हैं। वे जब कभी 'जनसंपर्क' के लिए निकलते हैं तो आम लोग शिष्टाचारवश उनकी थोड़ी-बहुत सराहना कर देते हैं। जब चुनावी जनसभाओं में भीड़ उमड़ती है तो नेतागण गद्गद हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस बार मैदान फतह कर ही लेंगे। चूंकि जनता भलीभांति जानती है कि नेतागण चुनावी मौसम में बड़े-बड़े वादे करते हैं। वे चुनाव जीतने के बाद उन पर कितने खरे उतरेंगे, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। जनसंपर्क में आश्वासन और जनसभा में उमड़ी भीड़ को वोट मिलने की गारंटी बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। जनता कई बिंदुओं के आधार पर वोट डालती है। राजनीति के बड़े-बड़े धुरंधर जनता का मिज़ाज समझने में मात खा जाते हैं। अगर इस साल हुए लोकसभा चुनाव से लेकर महाराष्ट्र-झारखंड विधानसभा चुनाव तक के एग्जिट पोल के आंकड़े देखें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि इनके ज्यादातर विश्लेषक हवा का रुख नहीं भांप पाए। चुनाव नतीजों के बाद चाहे कोई इसे अपने नेताओं का करिश्मा बताए या ईवीएम में खोट ढूंढे, हकीकत यह है कि आम जनता अब ज्यादा जागरूक है, वह नेताओं और एग्जिट पोल्स के विश्लेषकों को चौंकाने वाले नतीजे दे रही है। इसमें ईवीएम का 'दोष' सिर्फ इतना है कि अब उसके जरिए चुनाव हो रहे हैं। कोई नेता हार का ठीकरा उस पर फोड़ सकता है। अगर ये चुनाव मतपत्रों से होते तो भी हारने वाले कई नेता असंतुष्ट ही रहते। वे उस स्थिति में ये दावे करते हुए न्यायालय चले जाते कि 'हमारे मतपत्र फाड़ दिए गए या गायब कर दिए गए, हमारी पेटी चोरी हो गई या बदल दी गई, लिहाजा चुनाव कराने की कोई और प्रणाली लाई जाए!' हारने वाले राजनीतिक दल ईवीएम के आंकड़ों में हेरफेर के दावे खूब करते हैं, लेकिन आज तक न्यायालय में कोई पुख्ता प्रमाण पेश नहीं कर पाए। यह अलग बात है कि एक चुनाव हारने के बाद जब वे दूसरा चुनाव जीत जाते हैं या उसमें उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है, तब वे ईवीएम का विरोध नहीं करते, बल्कि नतीजों को खुशी-खुशी स्वीकार कर लेते हैं। जनता यह देख रही है, सबकुछ समझ रही है। अगर नेतागण जनता के बीच जाएं, उसकी आवाज बनें, समस्याओं का समाधान करें तो ईवीएम में खोट ढूंढने की नौबत ही न आए।

ट्वीटर टॉक

जोधपुर पुष्करणा समाज के रत्न गुरु गोविंद कल्ला जी का देहावसान कला, संगीत व साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

-राज्यवर्धनसिंह राठौड़

वंचित, शोषित एवं महिला वर्ग के सशक्तीकरण तथा सामाजिक उन्नयन हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान दिया ।

-भजनलाल शर्मा

आज केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत से दिल्ली में मुलाक़ात हुई। माननीय मंत्री महोदय से स्वदेश दर्शन, सास्की, एवं प्रसाद आदि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर शीघ्र स्वीकृति हेतु निवेदन किया।

-दीया कुमारी

प्रेरक प्रसंग

पुण्यकर्म का फल

चीन के जिन साम्राज्य के गोंग परिवार में फाह्यान का जन्म हुआ था। वह बौद्ध भिक्षु, यात्री, लेखक एवं अनुवादक थे। एक दिन विद्वान संत फाह्यान किसानों के साथ चावल की खेती कर रहे थे। तभी अकाल पीड़ितों का एक दल चावल की चोरी करने आया। उन्हें देखकर सभी भिक्षु भाग गए। फाह्यान ने चोरों से कहा कि अगर तुम्हें चावल चाहिए तो तुम ख़ुशी-ख़ुशी ले सकते हो पर उससे पहले यह जान लो कि तुम आज भूखे और इस स्थिति में क्यों हो। पिछले जन्म में तुमने कोई पुण्य कर्म और दान नहीं किए हैं, इसलिए तुम आज यहां हो। अभी भी तुम किसी दूसरे के हिस्से का चावल लेना चाहते हो तो तुम सदा आशाहीन ही रह जाओगे। मैं तुम्हारे भविष्य व अगले जन्म को लेकर चिंतित हूं। ऐसा कहकर वे बौद्ध मंदिर की ओर लौट गए। चोरों के जीवन पर इस बात का गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने फिर चोरी नहीं की। फाह्यान के इस व्यवहार को भिक्षुओं ने खूब सराहा। वे 399 ईसवी से लेकर 412 ईसवी तक भारत, श्रीलंका और नेपाल की यात्रा पर रहे। दस साल तक भारत में रहकर फाह्यान ने भारत की सभ्यता और संस्कृति पर नजर रखी और उसे यात्रा वृत्तांत में उद्धृत किया।

सामयिक

बाल विवाह मुक्ति बेटियों को खुला आसमान देगा

ललित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

देश में बाल विवाह की प्रथा को रोकने, बढ़ते बाल-विवाह से प्रभावित बच्चों के जीवन को इन त्रासद परम्परागत रूढ़ियों की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिये सरकार ने बाल-विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करके एक सराहनीय एवं स्वागतयोग्य उपक्रम से हिम्मत और बदलाव की मिसाल कायम की है। यह एक शुभ संकेत एवं श्रेयस्कर जीवन की दिशा है। यह किसी समाज के लिये बेहद नकारात्मक टिप्पणी है कि सदियों के प्रयास के बावजूद वहां बाल विवाह की कुप्रथा विद्यमान है। यहां यह विचारणीय तथ्य है कि समाज में ऐसी प्रतिगामी सोच क्यों पनपती है? क्यों लोग परंपराओं के खूंटे से बंधकर अपने मासूस बच्चों एवं बचपन से खिलवाड़ करते हैं? हमें यह भी सोचना होगा कि कानून की कसौटी पर अस्वीकार्य होने के बावजूद बाल विवाह की परंपरा क्यों जारी है? 'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' की शुरुआत दूरगामी मानवीय सोच से जुड़ा एक संवेदनशील आह्वान एक नई सुबह की आहट एवं क्रांति के विस्फोट की संभावना है। यह अभियान सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक संकल्प है, एक रोशनी है, एक मंजिल है, एक सकारात्मक दिशा है। एक वादा है देशभर में बाल विवाह पर जागरूकता फैलाने और समाप्त करने का। यह नये भारत-सशक्त भारत की बुनियाद है। बाल विवाह रोकने के तमाम कार्यों, योजनाओं और कानूनों के बावजूद अगर कामयाबी नहीं मिल रही है, तो जाहिर है, एक विशेष अभियान छेड़कर केन्द्र सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। यह राष्ट्रीय अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 जनवरी, 2015 को शुरू की गई प्रमुख योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की सफलता से प्रेरित है, जो विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए लड़कियों के बीच शिक्षा, कौशल, उद्यम और उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं बेटियों की आशाओं, आकांक्षाओं, संकल्पों से भरे सपनों की उड़ान को खुला आसमान देने में सक्षम होगा।

यह सुखद बात है कि बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 2029 तब बाल विवाह की दर को पांच प्रतिशत से नीचे लाने के मकसद से विशेष कार्य योजना बनाने का आग्रह किया है। यह बचपन की मासूमियत छीनने वाली 'बालविवाह' की बेड़ियों को तोड़ते हुए जागृति का एक शंखनाद किया है, एक समाज-क्रांति के बीज को रोपा गया है। सभी जानते हैं कि कम आयु के बच्चे अपने भविष्य के जीवन के बारे में परिपक्व फैसला लेने में सक्षम नहीं होते। साथ ही वे इस स्थिति में भी नहीं होते कि उनके जीवन पर थोपे जा रहे फैसले का मुखर विरोध कर सकें। उनके सामने आर्थिक स्वावलंबन का भी प्रश्न होता है। लेकिन अभिभावक क्यों इस मामले में दूरदृष्टि नहीं रखते? सही मायने में बाल विवाह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ही है। इसीलिये बाल-विवाह पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कानून परंपराओं से ऊपर है। कोर्ट का कथन तार्किक है कि जिन बच्चों की कम उम्र में शादी करा दी जाती है क्या वे इस मामले में तार्किक व परिपक्व सोच रखते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि यह समय की मांग है कि इस कानून को लागू करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए। इस बाबत उन समुदायों व धर्मों के लोगों को बताया जाना चाहिए कि बाल विवाह कराया जाना एक आत्मघाती कदम है। यह समझना कठिन नहीं है कि कम उम्र में विवाह कालांतर जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य के लिये भी घातक साबित होता है। उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती और वे अपनी आकांक्षाओं का कैरियर भी नहीं बना सकते। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कथन इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। केंद्रीय मंत्री ने उचित ही कहा है कि बाल विवाह मानवधिकारों का उल्लंघन और कानून के तहत अपराध है। अच्छी बात है, सरकार ने अब एक तरह से मान लिया है कि कानून को जितना काम करना था, उसने किया इसके आगे अब विशेष अभियान की जरूरत है। बाल विवाह को रोकने के लिए अकेले कानून के भरोसे न बैठते हुए ठोस जागृति-अभियान की अपेक्षा है। अब सरकार ने इस सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिये कमर कसी है, तो उसका स्वागत होना चाहिए एवं इस अभियान को व्यापक रूप देना चाहिए।

बाल विवाह की कुरीति को देश में व्यापकता से देखने को मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे खराब स्वरूप है। ठोस प्रयासों के बावजूद आज भी लगभग पांच में से एक लड़की का विवाह विधि सम्मत आयु 18 वर्ष से पहले कर दिया जाता है। किसी शहर में अगर एक विवाह सत्र में 1000 शादियां होती हैं, तो उनमें से 200 शादियों में दुल्हन की उम्र शादी लायक वैध नहीं होती। बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को यह भी बताया कि पिछले एक साल में लगभग दो लाख बाल विवाह रोके गए हैं। मतलब, सामाजिक संस्थाएं और पुलिस काम तो कर रही हैं, पर मंजिल अभी दूर है। बाल विवाह की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड, असम और आंध्रप्रदेश में है। देश में 300 ऐसे जिले हैं, जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। ऐसा लग रहा है, लोग बेटियों का जीवन तो बचा रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा भी देने लगे हैं, पर उन्हें अधिक पढ़ाने और आगे बढ़ाने पर उनका ध्यान नहीं है। बेटियों की जब कम उम्र में शादी होती हैं तो श्रम बल के रूप में न केवल उनकी उत्पादकता, बल्कि देश की क्षमता पर भी असर पड़ता है।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' की भविष्य दृष्टि से प्रेरित नये समाज की संरचना का दूरगामी प्रकल्प है। बच्चों पर बाल विवाह थोपना उनके अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का भी दमन है। भले ही मजबूरी में वे इस थोपे हुए विवाह के लिये राजी हो जाएं, लेकिन उसकी कसक जीवन पर्यंत बनी रहती है। जो उनके स्वाभाविक विकास में एक बड़ी बाधा बन जाता है। निश्चय ही इस बाबत बदलाव लाने के लिये कानून में जरूरी बदलाव लाने के साथ ही समाज में जागरूकता लाने की भी जरूरत है। इन सब दृष्टियों से यह अभियान सदियों से चली आ रही इस त्रासद परम्परा से मुक्ति का माध्यम बनेगा। पढ़ी-लिखी लड़की अगर विवाह-योग्य उम्र से ब्याही जाए, तो वह परिवार और समाज के लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। कम उम्र में विवाह से न केवल संतानों की गुणवत्ता बल्कि परिवार की आर्थिक, सामाजिक और मनावैज्ञानिक क्षमता पर भी असर पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बाल विवाह दर में सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक गिरावट दक्षिण एशियाई देशों में देखी गई है, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नए अभियान के अन्तर्गत इस परम्परागत विसंगति एवं विडम्बना को दूर करने के लिये व्यापक प्रयत्न किये जायेंगे। प्रारंभिक कार्ययोजना के अन्तर्गत बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल के जरिये बाल विवाह के विरोध में जागरूकता बढ़ाई जाएगी, बाल विवाह की शिकायत भी यहां दर्ज कराई जा सकती है एवं कार्य प्रगति की निगरानी भी की जाएगी। इस पोर्टल को सही ढंग से चलाया गया, गांवों और पंचायतों से जोड़ लिया गया, तो इसके सकारात्मक परिणाम आ सकते है। बाल विवाह मुक्त अभियान देश भर में युवा लड़कियों के सशक्तिकरण के सरकार के प्रयासों का प्रमाण है। यह प्रगतिशील और समतापूर्ण समाज सुनिश्चित कर हर बच्चे की क्षमता को पूर्णता से साकार करेगा। इस अभियान का संदेश 25 करोड़ नागरिकों तक पहुंचने की उम्मीद है। यह निर्विवाद है कि देश को विकसित बनाने के लिए महिलाओं की पूरी शक्ति का उपयोग जरूरी है और महिला शक्ति बढ़ाने के लिए बाल विवाह को रोकना ही होगा। आज सामाजिक सोच एवं ढांचे में परिवर्तन लाने की शुरुआत हो गयी है, इसमें सृजनशील सामाजिक संस्थाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण होगा। आवश्यकता है वे अपने सम्पूर्ण दायित्व के साथ आगे आये। अंधेरे को कोसने से बेहतर है, हम एक मोमबत्ती जलाएं।

मंथन

तेल पर सरकारी मुनाफे का खेल

बाल मुकुन्द ओझा

मोबाइल : 8949519406

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा आम जनता तक समुचित रूप से नहीं पहुंच रहा है, जबकि भारी भरकम टैक्स लगाकर सरकार जरूर अपना खज़ाना भर रही है। मौजूदा समय में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई है। इस दौरान ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस गिरकर 72.77 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं। वहीं डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल की बात करें तो यह गिरकर 68.68 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में पिछले पांच वर्षों के दौरान बड़ी गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन आम लोगों को महंगे पेट्रोल-डीजल के दामों से कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले पांच वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर अपना खजाना जरूर भर लिया है। संसद में प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में ये जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के बाद से लेकर मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही अप्रैल-जून तक पेट्रोल डीजल पर टैक्स के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों ने 36.58 लाख करोड़ रुपये की रिकार्ड कमाई की है। कुल टैक्स में 22,21,340 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के खजाने में गया है। जबकि राज्य सरकार ने अपना टैक्स यानी वैट लगाकर 14,37,015 लाख करोड़ रुपये वसूले हैं। यानि पेट्रोल-डीजल पर पांच वित्त वर्षों के दौरान वसूले गए 36.58 लाख करोड़ रुपये टैक्स में 60 फीसदी केंद्र सरकार ने वसूले हैं जबकि 40 फीसदी टैक्स राज्य सरकार के खजाने में गया। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण भारत में तेल विपणन कंपनियों को काफी लाभ हो रहा है। खउठ- की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां पेट्रोल पर 15 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 12 रुपये प्रति लीटर कमा रही हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों के प्रभावशाली वित्तीय प्रदर्शन को स्वीकार किया है। इन कंपनियों का संयुक्त लाभ 86,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले चुनौतीपूर्ण वित्त वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 16,014 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया। इसी तरह, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस अवधि के दौरान अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी थ्रूपुट, बिक्री मात्रा और शुद्ध लाभ हासिल किया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 26,673 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित लिया।

भारत की बात करतें तो आम चुनावों से पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर आम लोगों को राहत दी थी। पूरे देश में 15 मार्च 24 को पेट्रोल और डीजल की कीमत में प्रति लीटर दो रुपये की कटौती की गई। मई 2022 के बाद पहली बार देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में बदलाव किया गया था। आज की स्थिति की निष्पक्ष होकर समीक्षा करें तो सरकार मालामाल हो रही है और जनता कंगाल। आम उपभोक्ता आज भी महंगाई की बेरहम मार से पीड़ित होकर कराहने पर मजबूर है। सब्जी से लेकर खाने के तेल और दाल तक के भाव आसमान पर हैं और जनता धरती पर। हालांकि इससे देश की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार के लक्षण परिलक्षित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए यह अवधि सुकून भरी है। पेट्रोल-डीजल की कीमतें हाहाकार की स्थिति से नीचे आकर धीरे-धीरे आम आदमी की पकड़ में आने लगी हैं। मगर कीमतों में गिरावट का पूरा फायदा सरकार आम जनता को नहीं दे रही है। इसमें सरकार के अपने तर्क वाजिब हो सकते हैं मगर जनता अपने अच्छे दिनों का इन्तजार कर रही है। जनता चाहती है कि तेल के भावों में गिरावट का उसे पूरा फायदा मिलना ही चाहिये।

इस समय विश्व की अर्थव्यवस्था की मजबूत धुरी तेल ही है। विभिन्न देशों की सरकारों की राजस्व प्राप्ति का एक बड़ा हिस्सा पैट्रोलियम पदार्थों से हासिल होता है। सरकार का कहना है कि जब तेल की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं तब जनता को राहत प्रदान करने के लिए सरकार पर्याप्त मात्रा में अनुदान देती है जिसका फायदा जनता तक पहुंचता है। आज जब कीमतें गिर रही हैं तो सरकार को उत्पाद कर वसूलने का पूरा अधिकार है। सरकार का यह कथन पूरी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहला हित जनता का संरक्षित होना है। सरकार का यह दायित्व है कि वह अपनी जनता को विभिन्न रियायतें उपलब्ध कराकर लाभान्वित करे।

नजरिया

चिंताजनक है बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रही हिंसा

मनोज कुमार अग्रवाल

मोबाइल : 9219179431

बांग्लादेश में कट्टरपंथी लोगों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं का जीवन मुहाल कर दिया है हिन्दू समुदाय के लोगों पर हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली बांग्लादेश सरकार में हिन्दुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस्कॉन भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद भी चरमपंथी रुकने को तैयार नहीं हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से एक और मंदिर पर हमला किया गया है। ताजा मामला बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच मंगलवार (26 नवंबर) को चटगांव के तीन हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। जिसके बाद बांग्लादेश में जारी झड़प ने हिंसक रूप ले लिया। उल्लेखनीय है कि जिन तीन मंदिरों को निशाना बनाया गया है उनमें चटगांव के फिरंगी बाजार में लोकनाथ मंदिर, मनसा माता मंदिर और हजारी लेन में काली माता मंदिर शामिल है। बता दें कि ये घटना बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा का भाग है, जो कि 5 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से अत्यंत खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है। हिंदू समेत अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुए जब हिंदुओं ने इस्लामिक कट्टरपंथियों की ओर से किए गए संगठित हमलों के जवाब में बड़ी संख्या में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू किए गए. यह विरोध प्रदर्शन धार्मिक और सामाजिक संगठन इस्कॉन की ओर से आयोजित किए गए थे, जिसके अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं. इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे पर प्रमुख हिंदू नेता और इस्कॉन भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास को हिरासत में ले लिया।

भारत सरकार ने हिंदू धार्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दासब्रह्मचारी की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत नहीं दिए जाने के मामले पर गहरा रोष जताया। साथ ही पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के नहीं थमने का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से उठाया है। भारत ने बांग्लादेश सरकार से आह्वान किया है कि वह हिंदुओं समेत हर तरह के धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। भारत सरकार पिछले दो महीनों के दौरान कई बार ऐसे आग्रह कर चुकी है, लेकिन जब से शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया गया है तब से हिंदुओं के उत्पीड़न का मामला बढ़ता जा रहा है। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद युनूस इस बारे में उल्टा भारत पर ही आरोप लगाते रहे हैं कि हिंदुओं पर हमले के मुद्दे को भारतीय मीडिया बढ़ा-चढ़ा कर बता रहा है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जोत के नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी और उनको जमानत नहीं दिए जाने के घटनाक्रम को लेकर हमें गहरी चिंता है। यह घटना हिंदुओं व दूसरे अल्पसंख्यकों पर हुए कई हमलों के बाद सामने आई है। अल्पसंख्यकों के घरों और उनके कारोबार को तबाह करने, लूटने, मंदिरों में मूर्तियों को खंडित करने आदि घटनाओं के ठोस साक्ष्य हैं। बांग्लादेश में हिंदू समूह सम्मिलिता सनातनी जोत के नेता एवं इस्कान ट्रस्ट के सचिव रहे चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के विरोध में राजधानी ढाका और चटगांव समेत कई जगहों पर लोग सडकों पर उतरे और उनकी रिहाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई और आंसू गैस के गोले दागे गए। एक वकील की मौत भी हो गई। एक अदालत ने चिन्मय को जमानत देने से इन्कार कर दिया। उनको देशद्रोह के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, ईसाई, एकता परिषद ने बताया कि हिंदुओं के साथ- साथ ईसाइयों और बौद्धों के खिलाफ हत्या, छेड़छाड़ और अपहरण समेत हमलों की 2010 घटनाएं हुई हैं। बांग्लादेश में हिंदू समूह सम्मिलिता सनातनी जोत के नेता एवं इस्कान ट्रस्ट के सचिव रहे चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के खिलाफ प. बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने मंगलवार को राज्य विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी भाजपा विधायकों ने चिन्मय दास की तस्वीर वाली तख्तियां लेकर विधानसभा परिसर से विरोध मार्च निकाला और उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हुए मुख्य गेट के बाहर एकत्रित होकर नारेबाजी की। इस दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु ने चिन्मय दास की गिरफ्तारी की निंदा की और उन्हें बिना शर्त शीघ्र रिहा करने की मांग करते हुए बांग्लादेश सरकार को पेट्रापोल सीमा के जरिए सभी तरह के व्यापार और आवाजाही को ठप करने की कड़ी चेतावनी दी।

बांग्लादेश में आये राजनीतिक बदलाव के कारण वहां के हिन्दुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन से वहां कट्टरपंथियों का बोलबाला हो गया है और वर्तमान सरकार की विदेशी नीति में आये परिवर्तन के कारण सामरिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ काफी अच्छे संबंध हो गए हैं। बांग्लादेश में हिन्दुओं और भारत विरुद्ध जो हो रहा है या कहा जा रहा है उसके पीछे पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान के पीछे चीन है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए भारत को अपनी विदेश नीति के साथ-साथ अपनी आर्थिक व राजनीतिक नीतियों पर भी समयनुसार परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों देश भारतीय सीमाओं पर और भारत के भीतर भी समस्याएं बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। भारत को अति सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है। तत्काल रूप से तो बांग्लादेशी हिन्दुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ संपर्क कर अपना रोष प्रकट करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश में हिन्दुओं के साथ हो रहे अत्याचारों को उठाना चाहिए।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता ।– **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

प्रवासी विशेषज्ञों ने ट्रूडो की आप्रवासन नीति पर उठाए सवाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

वैंकूवर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर आप्रवासन नीति के बारे में बताया। उन्होंने इस नीति के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करते हुए दावा किया कि इससे कनाडा में लगभग 20 प्रतिशत तक आप्रवासन को कम किया जा सकेगा। ट्रूडो ने यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया है जब आप्रवासन के मुद्दे पर उनका जनसमर्थन कम होता जा रहा है और दल के नेता के पद से उनके इस्तीफा दिए जाने की मांग की जा रही है। वहीं, देश में आगामी संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी (लिबरल पार्टी) की जीतने की संभावनाएं भी कम होती नजर आ रही हैं। दो हजार के दशक के प्रारंभ से ही कनाडा के लोगों ने आप्रवासन पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा, लेकिन धीरे-धीरे अब लोगों की राय बदल रही है। हालांकि अब भी कनाडा के लोगों की प्राथमिकताएं अर्थव्यवस्था, आवास और स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित है, लेकिन जब उनसे आप्रवासन के बारे में पूछा जाता है तो अधिकतर लोग यही कहते हैं कि देश में अप्रवासियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कनाडा में 1957 के बाद साल 2022 और 2023 में सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि देखी गई। देश में 1999 से जनसंख्या बढ़ने का अहम कारण अन्य देशों से आने वाले लोग ही रहे हैं। वहीं, इन दोनों साल में कनाडा की जनसंख्या बढ़ने का कारण अस्थायी निवासी ही हैं, जिसमें अप्रवासी श्रमिक और अंतरराष्ट्रीय छात्र शामिल हैं। ट्रूडो ने वीडियो संदेश में दावा किया कि अधिकतर अप्रवासी ''अपने घर लौट जाते हैं और वे कभी भी लंबे समय तक अप्रवासी'' नहीं बने रहते। कनाडा में साल 2023 के मध्य से अस्थायी निवासियों खासकर अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आवास संबंधी परेशानियों का कारण माना जाने लगा। कनाडा सरकार अध्ययन परमिट की सीमा तय करके और कार्य परमिट को प्रतिबंधित करके अस्थायी निवासियों की संख्या को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तब भी सरकार की दो-चरणीय आव्रजन नीति अहम है। कई अस्थायी निवासी स्वाभाविक रूप से कनाडा में ही रहना चाहते हैं।

ट्रूडो ने दावा किया, ''बहुत से कॉलेज और विश्वविद्यालय अपनी आय बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं... क्योंकि वे इन छात्रों से डिग्री के लिए हजारों डॉलर अधिक वसूलते हैं।'' हालांकि अप्रवासियों की बढ़ती संख्या के लिए केवल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

ट्रूडो ने कनाडा की 2014-19 और 2019-24 की संघीय अंतरराष्ट्रीय शिक्षा रणनीतियों का भी जिक्र नहीं किया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय छात्रों के आर्थिक योगदान पर जोर दिया गया है।

कनाडा की सार्वजनिक उच्च शिक्षा को देखते हुए अब समय आ गया है कि अधिक संसाधनों की मांग की जाए तथा इसके मूल्य की रक्षा की जाए न कि ध्यान भटकाने के लिए किसी पर उंगली उठाई जाए। ट्रूडो ने वीडियो में अंत में बताया कि ''कुछ अस्थायी निवासी वीजा की अवधि समाप्त होने पर कनाडा में रहने के लिए शॉर्टकट के रूप में हमारी शरण प्रणाली की ओर रुख कर सकते हैं, लेकिन ''यदि वे उचित दस्तावेज या उचित कारण नहीं बता पाए तो उन्हें घर भेज दिया जाएगा।''

कनाडा के साथ भारत के संबंध आज भी हैं चुनौतीपूर्ण : सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि कनाडा के साथ भारत के संबंध चुनौतीपूर्ण रहे हैं और आज भी हैं क्योंकि वहां की सरकार द्वारा ऐसे चरमपंथी एवं अलगाववादी तत्वों को राजनीतिक आश्रय प्रदान किया जाता है जो भारत विरोधी एजेंडे का समर्थन करते हैं।

विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक दूसरे की चिंताओं, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान किसी भी स्थिर द्विपक्षीय संबंध के लिए आवश्यक शर्तें हैं।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के अब्दुल वहाब ने विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा था कि क्या यह सच है विगत में कनाडा के साथ भारत के संबंध खराब हुए हैं।

इसके जवाब में सिंह ने कहा, ''कनाडा के साथ भारत के संबंध चुनौतीपूर्ण रहे हैं और आज भी हैं। क्योंकि कनाडा सरकार द्वारा मुख्यतः ऐसे चरमपंथी एवं अलगाववादी तत्वों और ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक आश्रय प्रदान किया जाता है, जो भारत विरोधी एजेंडे का समर्थन करते हैं और भारत की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालने वाले हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कनाडा की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''एक दूसरे की चिंताओं क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान किसी भी स्थिर विपक्षीय संबंध के लिए आवश्यक शर्तें हैं।''

सिंह ने बताया कि इस संबंध में भारत सरकार ने कनाडा सरकार से बार-बार आग्रह किया है कि चरमपंथी एवं अलगाववादी तत्व अपने कार्यों के लिए उनकी भूमि का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने ऐसे तत्वों के त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने का भी बार-बार आग्रह किया है।

सिंह ने बताया, ''ऐसे तत्व हमारे नेताओं की हत्या का महिमामंडन करने, वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व और राजनयिकों को धमकियां देने, पूजा स्थलों का अनादर और वहां तोड़फोड़ करने में शामिल हैं।''

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कनाडा की सरकार से यह भी कहा कि वह तथाकथित 'जनमत संग्रह' आयोजित करके भारत के विखंडन का समर्थन करने से अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों को रोके।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कनाडा में रहने, काम करने और पढ़ाई करने वाले भारतीय नागरिकों का कल्याण और सुरक्षा भारत सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ''कनाडा में भारतीय नागरिकों के सामने आने वाले समस्याओं को तुरंत कनाडा के अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है ताकि उनका तुरंत समाधान किया जा सके।'' एक अन्य सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि दोनों सरकारें द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति के बारे में एक दूसरे के संपर्क में है। कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश राज्यमंत्री ने कहा कि ''जहां अधिकारी हमारे राजनयिकों को और राजनयिक संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम रहे हैं वहीं उन्होंने हाल ही में अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों के हिंसक कृत्यों से हमारे वाणिज्य तथा शिविरों को सुरक्षा कवर प्रदान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।'' उन्होंने कहा कि कनाडा ने भारतीय राजनयिकों और वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को भारतीय और कनाडाई नागरिकों विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लाभ के लिए समुदाय के सदस्यों की मदद से विशेष रूप से आयोजित शिविरों में बहु प्रतीक्षित वाणिज्य दूतावास और पासपोर्ट संबंधी सेवाएं प्रदान करने से रोक दिया है, जो अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र चाहते हैं। उन्होंने कहा, ''अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ जुड़ाव के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमेशा रचनात्मक और ईमानदार रहा है, जिसमें आपसी विश्वास, सम्मान और एक दूसरे की चिंताओं को समझाने पर जोर दिया गया है। भारत के दृष्टिकोण से इसके प्रत्येक द्विपक्षीय संबंध अपनी योग्यता पर खड़े हैं और अन्य देशों के साथ संबंधों से स्वतंत्र है।''

सिंह ने बताया कि लगभग 18 लाख भारतीय-कनाडाई (कनाडा की आबादी का लगभग 4.7 प्रतिशत)और लगभग 4,27,000 भारतीय छात्रों सहित 10 लाख अनिवासी भारतीयों के साथ कनाडा विदेश सबसे बड़े भारतीय प्रवासी स्थलों में से एक है। उन्होंने बताया कि साल 2023 में भारत-कनाडा द्विपक्षीय व्यापार 9.36 अरब डॉलर था, जिसमें भारत का कनाडा को निर्यात 5.56 अरब डॉलर और कनाडा से आयात 3.8 अरब डॉलर है।

सिंह ने कहा कि निवेश के मामले में कनाडा पेंशन फंड में भारत का हिस्सा उनके एशिया प्रशांत निवेश पोर्टफोलियो का लगभग 25 प्रतिशत है और कनाडा 3.9 अरब डॉलर के संचयी एफडीआई के साथ भारत में 17वां सबसे बड़ा निवेशक है।

ज़ी सिनेमा ने रिलीज किया 'किसको था पता' का ट्रेलर

मुंबई/एजेन्सी

ज़ी सिनेमा ने फिल्म 'किसको था पता' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। 'किसको था पता' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ज़ी सिनेमा की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म को रत्ना सिन्हा ने निर्देशित किया है , जो 'शादी में ज़रूर आना' और 'मिडल क्लास लव' जैसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए मशहूर हैं। इस फिल्म में अक्षय ओबेरॉय, अशनूर कौर और आदिल खान नज़र आएंगे। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे कुछ फैसले हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं।

निर्देशक रत्ना सिन्हा ने कहा, अपनी पिछली फिल्मों में रिश्तों और जज़्बातों को दिखाने के बाद, मैं इस बार रिश्तों की गहराई और उनकी अनिश्चितता को लेकर एक अलग कहानी बताना चाहती थी। 'किसको था पता' उन फैसलों की कहानी है, जो हमारी ज़िंदगी को दिशा देते हैं। इस फिल्म के सभी कलाकारों ने शानदार काम किया है, और मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस फिल्म को बेहद पसंद करेंगे।

अशनूर कौर ने कहा, श्रेया का किरदार निभाना मेरे लिए एक यादगार अनुभव रहा। वो एक मजबूत और भावुक लड़की है, जो प्यार और उसे खो देने के दर्द से गुज़र रही है। वो अपने अतीत और भविष्य के बीच उलझी हुई है। उसकी कहानी खुद को फिर से खोजने की है। 'किसको था पता' की कहानी हर उस इंसान से जुड़ती है, जिसने प्यार में मुश्किल फैसले लिए हों। मुझे उम्मीद है कि दर्शक श्रेया की कहानी से जुड़ पाएंगे और इसे महसूस करेंगे।

अक्षय ओबेरॉय ने कहा, देवांश का किरदार प्यार, दिल टूटने और फिर खड़े होने की कहानी है। इस किरदार की गहराई और उसके सामने खड़े फैसलों ने मुझे बहुत आकर्षित किया। 'किसको था पता' एक मॉडर्न लव स्टोरी है, लेकिन इसमें उन जज़्बातों का ज़िक्र है, जो हमेशा दिलों में रहते हैं। यह रिश्तों की उलझनों को दिखाती है। मुझे यकीन है कि दर्शक देवांश की कहानी को जरूर पसंद करेंगे। आदिल खान ने कहा, धैर्य का किरदार निभाना मेरे लिए अलग अनुभव था।वो मस्ती भरा और आज़ाद ख्यालों वाला इंसान है, जिसके कई पहलू हैं। 'किसको था पता' की कहानी ज़िंदगी के कुछ मुश्किल फैसलों और उनके नतीजों के बारे में है। मुझे लगता है कि हर दर्शक इस कहानी में अपनी झलक पाएगा। यह फिल्म हमारे लिए दिल से की गई मेहनत का नतीजा है। 'किसको था पता' का प्रीमियर इस क्रिसमस, 25 दिसंबर को ज़ी सिनेमा पर होगा।

सुमित कौल 'तेनाली रामा' में गिरगिट की भूमिका में आयेंगे नजर

मुंबई/एजेन्सी

टेलीविज़न एक्टर सुमित कौल तेनाली रामा में गिरगिट की भूमिका निभाते नज़र आने वाले हैं। सोनी सब का लोकप्रिय शो तेनाली रामा एक रोमांचक मोड़ के साथ टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी करने वाला है। इसमें एक नया किरदार गिरगिट पेश किया गया है, जिसे प्रतिभाशाली सुमित कौल निभा रहे हैं। गिरगिट सिर्फ एक और विरोधी नहीं है; वह एक जटिल किरदार है, जिसका भेस बदलने का हुनर और चालाक स्वभाव उसे प्रिय दरबारी तेनाली रामा के लिए एक बड़ी चुनौती बनाता है।

गिरगिट की प्रतिभा मानव स्वभाव को पढ़ने की उसकी अद्भुत क्षमता में निहित है। भेस बदलने की अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए वह किसी भी भूमिका में ढल जाता है, चाहे वह एक साधारण नौकर हो या एक महान दरबारी। इस भूमिका पर सुमित कौल ने कहा, गिरगिट एक अनूठा किरदार है। मैंने

आज तक ऐसा किरदार नहीं निभाया है। जटिलताओं से घिरा हुआ, हमेशा साजिशें रचने वाला और अप्रत्याशित हरकत करने वाला। भेस बनाकर माहौल में शामिल होने और अपने मनचाहे तरीके से स्थिति को अपने पक्ष में करने की क्षमता उसे एक बड़ा खलनायक बनाती है।

उन्होंने कहा, क्रिएटिव टीम ने गिरगिट के लुक में आकर्षक विवरण जोड़े हैं, जैसे गिरगिट का टैटू और उसकी प्रतीकात्मक कांच की आंख, जो उसे और भी अधिक डायनामिक बनाती है। वह एक ऐसा खलनायक है जिसकी ओर दर्शक आकर्षित होंगे, उसके डार्क स्वभाव के बावजूद और मैं उसे जीवंत करने को लेकर रोमांचित हूं। सुमित कौल ने कहा, गिरगिट को जो चीज वास्तव में आकर्षक बनाती है, वह है भेस बदलने की उसकी महारत। वह सहजता से पूरी तरह से अलग-अलग व्यक्तित्वों में बदल सकता है - एक दरबारी, एक नौकर, या एक रईस - जिससे उसे पहचानना लगभग असंभव हो जाता है। यह गिरगिट जैसी क्षमता उसे सत्ता संरचनाओं में घुसपैठ करने और अपने आस-पास के लोगों को बरगलाने, उनसे अपनी इच्छा के अनुसार काम कराने की अनुमति देती है। चाहे वह साफ नजरों में छिपा हो या छाया से काम कर रहा हो, गिरगिट की उपस्थिति हमेशा एक खतरा है। तेनाली रामा इस दिसंबर से हर सोमवार से शनिवार रात 8:00 बजे सोनी सब पर प्रसारित होगा।

कुछ साल में पाकिस्तान रक्षा निर्यात से 30 अरब डॉलर कमाएगा: सरकार

कराची/भाषा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश आने वाले वर्षों में मित्र देशों को रक्षा उत्पादों और उपकरणों के निर्यात से लगभग 30 अरब डॉलर कमा सकता है।

रक्षा उत्पादन सचिव लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) चिराग हैदर ने पीटीआई-भाषा से कहा कि पाकिस्तान ने उन्नत ड्रोन, लड़ाकू जेट, वाणिज्यिक और लॉजिस्टिक जहाज, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और रडार सहित रक्षा उत्पादों और उपकरणों के निर्यात के लिए अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और सेमिनार (आईडीएएस-2024) के दौरान 82 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

हैदर ने कहा कि पिछले सप्ताह कराची में कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित आईडीईएस का 12वां संस्करण एक बड़ी सफलता थी और कई संभावित निर्यात समझौतों के साथ समाप्त हुआ।

प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए अमेरिका, रूस, चीन, तुर्किये, ईरान, इटली, ब्रिटेन और अजरबैजान सहित 55 से अधिक देशों के रक्षा विनिर्माताओं और प्रदर्शकों ने प्रतिनिधिमंडल भेजे।

हैदर ने कहा, पाकिस्तान ने 30 अरब डॉलर के संभावित निर्यात ऑर्डर के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।''

'बीवी नंबर 1' के दोबारा रिलीज होने से पहले सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म का ट्रेलर

मुंबई/एजेन्सी

हिट कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1 सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है ऐसे में यह फिल्म 90 के दशक के प्रसंशकों के लिए किसी ट्रीट से काम नहीं है । इस फिल्म में सलमान खान, करिश्मा कपूर, सुष्मिता सेन, अनिल कपूर और तब्बू जैसे बेहतरीन कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नज़र आये थे। फिल्म के बड़े पर्दे पर दोबारा रिलीज होने से पहले सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर 'बीवी नंबर 1' का ट्रेलर रिलीज किया, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई। इसके अलावा, उन्होंने फिल्म के कलाकारों और क्रू को भी धन्यवाद दिया। फिल्म के दोबारा रिलीज होने के बारे में बात करते हुए सलमान खान ने कहा, बीवी नंबर 1 मेरे दिल में एक खास जगह रखती है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसने 90 के दशक में दर्शकों को जोड़ा और आज भी कई चेहरों पर मुस्कान लाती है। डेविड के साथ काम करना और उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और वाशु जी के विजन ने इस फिल्म को वह बनाया जो यह है। जैसे ही खान ने ट्रेलर शेयर किया, अभिनेता के कई प्रशंसकों ने फिल्म के फिर से रिलीज होने के लिए उत्साह और उत्सुकता के साथ उनके कमेंट सेक्शन को भर दिया। 1999 में शुरू में रिलीज़ हुई 'बीवी नंबर 1' को अपने असाधारण हास्य, कहानी, प्रदर्शन और गानों के लिए दर्शकों और समीक्षकों से पॉजिटिव समीक्षा मिली थी और यह साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी। फिल्म निर्माता डेविड धवन द्वारा निर्देशित और वाशु भगनानी की पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित, 'बीवी नंबर 1' को कई नामांकन मिले और पुरस्कार समारोहों में कई पुरस्कार जीते।

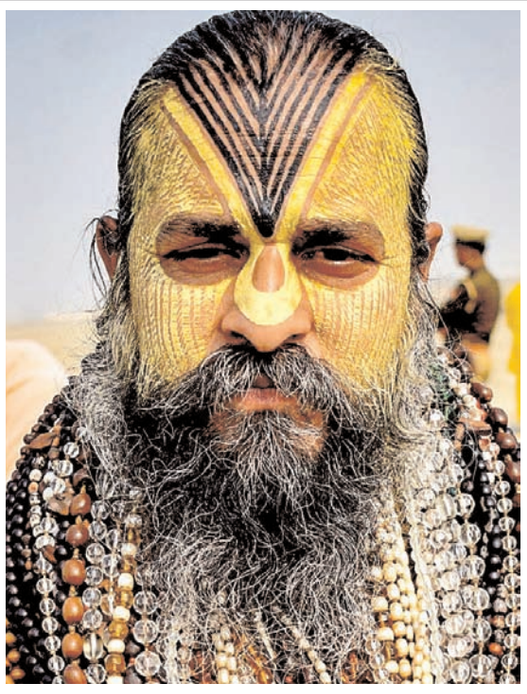

प्रयागराज में गुरुवार को महाकुंभ मेला 2025 से पहले 'रुद्राक्ष' पहने एक साधु फोटो खिंचवाते हुए।

राशि खन्ना ने अपने जन्मदिन पर पौधे लगाए

मुंबई/एजेन्सी

अपने जन्मदिन से पहले, पैन-इंडिया स्टार राशि खन्ना ने एक सार्थक और पर्यावरण-अनुकूल भाव के साथ एक विशेष समारोह आयोजित किया। इस अवसर की शुरुआत उन्होंने वृक्षारोपण अभियान में भाग लेकर की, जहाँ उन्होंने 100 बच्चों के साथ पौधे लगाए।

यह विचारशील पहल भामला फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी, जो ग्रह को वापस देने की राशि की प्रतिबद्धता को उजागर करती है और युवा पीढ़ी को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। उनके इस अद्वितीय और प्रभावी तरीके से अपने जन्मदिन की शुरुआत करने का निर्णय इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि वह पृथ्वी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कितनी गंभीरता से लेती हैं।

हाल ही में, राशि ने 'द साबरमती रिपोर्ट' में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक प्रशंसा अर्जित की। उन्होंने निडर पत्रकार अमृता गिल की भूमिका निभाई, एक ऐसी भूमिका जिसने एक अभिनेत्री के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा और गंभीरता को प्रदर्शित किया। यह फिल्म, जिसमें विक्रांत मैसी भी थे, गोधरा के पास घटित दुखद सबर्मति एक्सप्रेस घटना पर आधारित थी।

उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और राशि की दमदार अभिनय ने कहानी में एक महत्वपूर्ण भावनात्मक अहमियत जोड़ी, जिससे यह एक यादगार सिनेमा अनुभव बना। इसके अलावा, राशि अपनी आगामी फिल्म 'तलाखों में एक' में विक्रांत मैसी के साथ फिर से जुड़ेंगी, जो उनके सफल सहयोग को आगे बढ़ाएगा। उनके पास पाइपलाइन में एक रोमांचक तेलुगु फिल्म 'तेलुसु कड़ा' भी है। जैसा कि राशि ने ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन दोनों जगह प्रभावशाली विकल्प चुनना जारी रखा है, उनका जन्मदिन से पहले का जश्न उनके ग्राउंडेड वैल्यू और सार्थक कारणों के प्रति उनके समर्पण के प्रमाण का प्रतीक बन गया है।

अगले वर्ष रिलीज होगी अक्षय कुमार- प्रभास की फिल्म 'कन्नप्पा'

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार और दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फ़िल्म 'कन्नप्पा' 25 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी। फिल्म कन्नप्पा को लेकर फैंस का इंतजार खत्म हो गया है। अक्षय कुमार और प्रभास पहली बार एक साथ एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का एक पोस्टर जारी किया गया है,इसमें भगवान शिव के त्रिशूल के साथ रिलीज डेट अनाउंस की गई है। फिल्म कन्नप्पा इसी साली यानी 2024 में रिलीज होगी, लेकिन अब जो रिलीज डेट अनाउंस हुई वो अगले साल 2025 की है। यह फ़िल्म 25 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी।

फिल्म की कहानी भगवान शिव के भक्त कन्नप्पा जी की रियल कहानी पर आधारित है। तेलुगु लोककथाओं में से एक है कन्नप्पा की कहानी।

यह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। कन्नपा एक नास्तिक और निडर योद्धा थे, लेकिन बाद में वो भगवान शिव के परम भक्त बन गए। ये भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे की इन्होंने अपनी आंख निकाल कर भगवान शिव को समर्पित कर दी थी।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

www.dakshinbharat.com
epaper.dakshinbharat.com

बेंगलूरु | शुक्रवार | 29-11-2024 /dakshinbharat /dakshinbharat DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT HINDI DAILY

RNI No. 58061/93. Regn No.:
RNP/KA/BGS/2050/2018-2020
Posted at Bengaluru PSO
Mysore Road Bengaluru-560 026.

शहर के वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ हनुमंतनगर के तत्वावधान में एवं साध्वीश्री सुशीलाकंवरजी के सान्निध्य में श्रमण संघीय खद्दरधारी गुरुदेव श्री मिश्रीमलजी की 31वीं पुण्यतिथि पर त्रिदिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम के तहत आखिरी दिन गुरुवार को जैन स्थानक हनुमंतनगर में 2-2 सामायिक साधना के साथ सामायिक दिवस के रूप में तप - त्याग के साथ मनाई गई।

कन्नड़ राज्योत्सव के मौके पर बांटी गई शिक्षण सामग्री

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। शहर के विनायक गेलेरा बालगा संस्था द्वारा रंगनाथपुरा कामाक्षीपाल्या के महादेश्वर देवस्थान मार्ग पर कर्नाटक राज्योत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि महेंद्र मुणोत ने मां भुवनेश्वरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मुणोत व अन्य आयोजकों ने जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की तथा अन्नदान कार्यक्रम में सेवा दी। इस मौके पर आयोजकों ने मुणोत का सम्मान किया।

लब्धिधारी, उग्रविहारी, घोरतपस्वी संत थे गुरु मिश्रीमल : साध्वीश्री सुशीलाकंवर

संतश्री मिश्रीमल का पुण्य स्मृति दिवस तप-त्यागपूर्वक मनाया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ हनुमंतनगर के तत्वावधान में एवं साध्वीश्री सुशीलाकंवरजी के सान्निध्य में श्रमण संघीय खद्दरधारी गुरुदेव श्री मिश्रीमलजी की 31वीं पुण्यतिथि पर त्रिदिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम के तहत आखिरी दिन गुरुवार को जैन स्थानक हनुमंतनगर में 2-2 सामायिक साधना के साथ सामायिक दिवस के रूप में तप - त्याग के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दो-दो सामायिक साधना के रूप में गुरुदेवश्री मिश्रीमलजी के गुरु चरणों में सामायिक व्रत तप-त्याग की अनमोल भेंट अर्पण की। साध्वीश्री सुशीलाकंवरजी ने घोर तपस्वी श्री मिश्रीमलजी म. सा. के बहुआयामी व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर सारगर्भित प्रकाश डालते हुए गुरुदेव के प्रेरक संयमी जीवन से जुड़ें अनेक संस्मरण सुनाए।

उन्होंने कहा कि संयम में उत्साह होना अनिवार्य है। वरना साधक का जीवन मुक्ति के प्रगतिपथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने संयम के तीन आयामों- संयम में उत्साह, प्रवाह और निर्वाह के माध्यम से पूज्य गुरुदेव की संयमी जीवन के गुणों की विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख किया। वे लब्धिधारी, उग्रविहारी, घोरतपस्वी व आतापनाबारी आत्मार्थी महासाचक संतरत्न शिरोमणि थे। संचालन करते हुए संघ के मंत्री सुरेश धोका ने भी गुरु गुण स्मरण किया।

साध्वीश्री जयश्रीजी म सा ने भी गुरुदेव के गुणगान करते हुए कहा कि मिश्रीमलजी उत्साही, संयम के प्रति दृढ़ता वाले संत थे। इस अवसर पर संघ अध्यक्ष गौतमचंद सिंघवी, कल्याणसिंह बुरड़, धार्मिक शिक्षक संजयकुमार कचोलिया, महावीर बुबकिया, प्रभा गुलेच्छा एवं त्यागराजनगरसंघ के पदाधिकारी भी उपस्थित

मेरे घर में संगीत सिर्फ कला नहीं था, जीवन जीने का तरीका था : हरिहरन

नई दिल्ली/भाषा। मुंबई में पले-बढ़े मशहूर गायक हरिहरन अपने बचपन में अक्सर रागों के स्वरों, हवा में चाय की खुशबू और परिवार में कर्नाटक संगीत की धुनों पर गहन चर्चाओं के बीच जागते थे।

उनके लिए घर की चार दीवारों के बाहर की दुनिया भी कुछ ऐसी ही थी, जिसके केंद्र में संगीत था। क्योंकि मुंबई शहर ने हरिहरन को मंदिरों में भजनों की धुनों, गणेश चतुर्थी के दौरान सड़क पर होने वाली प्रस्तुतियों, बॉलीवुड के आकर्षण और शास्त्रीय संगीत समारोहों से परिचित कराया।

शास्त्रीय संगीतज्ञ एच ए एस मणि और अलामेलु मणि के घर 1955 में जन्मे हरिहरन के लिए संगीत एक स्वाभाविक पसंद की तरह था।

हरिहरन ने 'पीटीआई-भाषा' को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ''मेरे घर में संगीत सिर्फ कला नहीं था, यह जीवन जीने का एक तरीका था। शास्त्रीय संगीतज्ञों के परिवार में जन्म लेना और बड़ा होना एक आशीर्वाद की तरह था, जिसे मैं बचपन में पूरी तरह से समझ नहीं पाया था।'' उन्होंने कहा, ''मेरी शुरुआती यादें सुबह के शुरुआती घंटों में रियाज के दौरान रागों के स्वरों और हवा में फैलती चाय की खुशबू से भरी हैं।''

वह 30 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अपने '50-ईयर लीगेसी कॉन्सर्ट' के

साथ संगीत में अपने पांच दशक के शानदार करियर का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा, ''यह जुनून, दृढ़ता और अपने दर्शकों के साथ गहरे जुड़ाव की यात्रा रही है। संगीत उद्योग में 50 वर्षों की यात्रा को याद करना अवास्तविक लगता है। यह संगीत कार्यक्रम उतना मेरी विरासत को सम्मान देने के लिए नहीं है, जितना मेरे श्रोताओं के साथ मेरे अविश्वसनीय लगाव का जश्न है।''

हरिहरन ने कहा कि उनका प्रारंभिक शास्त्रीय संगीत प्रशिक्षण, फिल्म संगीत, गजल, भजन और उनके फ्यूजन बैंड 'कोलोनियल कजिन्स' में भविष्य के उपक्रमों के लिए एक आधार बन गया। उन्होंने कहा, ''इसने मुझे प्रयोग करने, शैलियों का मिश्रण करने और संगीत की दुनिया के अनुकूल होने का आत्मविश्वास दिया। उदाहरण के लिए, फिल्म संगीत को ही ले लीजिए। इसके लिए विविधता की आवश्यकता होती है; एक दिन आप कोई रूमानी धुन गा रहे होते हैं, और अगले दिन, आप एक जोश वाला गीत प्रस्तुत कर रहे होते हैं। शास्त्रीय प्रशिक्षण ने मुझे उन बदलावों को सहजता से करने में मदद की।''

गायक ने 1978 में मुजफ्फर अली की 'गमन' में 'अजीब सा नेहा' गीत के साथ अपने पार्श्व गायन करियर की शुरुआत की और उसके बाद फिल्म संगीत ने उनके करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

लेकिन फिल्मों में गाना शुरू करने से पहले, वह 1974 से ही टेलीविजन पर गजल गा रहे थे।

हरिहरन ने कई भाषाओं की फिल्मों में कुछ सबसे यादगार गाने गाए हैं, जिनमें रोजा, जींस, हमसे है मुकाबला, बॉम्बे, रंगीला, खामोशी: द म्यूजिकल, माचिस, दिल तो पागल है, जिद्दी, इरुवर, ताल, गुरु, एंथिरन, शिवाजी, और सीता रामम हैं।

पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित हरिहरन ने कहा, मेरे और मेरे करियर के लिए, फिल्म संगीत निश्चित रूप से एक पड़ाव था, लेकिन यह अन्य शैलियों - गजल, भजन, फ्यूजन संगीत और लाइव प्रस्तुतियों में मेरा प्रवेश भी था जिससे मुझे एक विरासत बनाने में मदद मिली। उन्होंने कहा, ''मुंबई ने मुझे हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया और इतने सालों बाद भी यह प्रेरणा मुझे रास्ता दिखाती रही है।'

बोलीविया में सबसे दुर्लभ वस्तुओं में से एक बनता जा रहा है ईंधन

एल आल्टो (बोलीविया)। बोलीविया में ईंधन तेजी से सबसे दुर्लभ वस्तुओं में से एक बनता जा रहा है। दक्षिण अमेरिका में प्राकृतिक गैस के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक बोलिविया में पेट्रोल पंपों के बाहर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। कुछ वाहन तो कई दिनों तक कतारों में खड़े नजर आते हैं। लोगों के बीच निराशा बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि विक्टर गार्सिया जैसे चालक अब अपने कतारों में खड़े ट्रकों के आसपास ही खाते-पीते तथा सोते हैं। गार्सिया (66) ने कहा, '' हमें नहीं पता कि क्या होगा? यकीनन हमारी स्थिति और भी खराब होने वाली है,।''

अन्य चालक रामिरो मोरालेस (38) ने कहा, '' कतारें लगातार लंबी होती जा रही हैं।'' उन्होंने बताया कि मंगलवार को चार घंटे कतार में खड़े रहने के बाद उन्हें शौचालय जाना था लेकिन उन्हें डर था कि कतार से हटने पर उनको अपनी जगह खोनी पड़ सकती है।

मोरालेस ने कहा, '' लोग अब थक चुके हैं।''

बोलीविया में ईंधन की कमी की समस्या ऐसे समय में उत्पन्न हुई है जब देश का विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है। इस कारण बोलीविया के लोगों को अमेरिकी डॉलर नहीं मिल पा रहे हैं। आयातित सामान जो कभी आम थे, अब दुर्लभ हो गए हैं।

सांता क्रूज के पूर्वी प्रांत में गेब्रियल रेने मोरेनो स्वायत्त विश्वविद्यालय के 'वाइस-रेक्टर' रीनेरियो वर्गास ने कहा, '' हम ईंधन, डॉलर की कमी और खाद्य कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए प्रभावी समाधान चाहते हैं।''

इन तमाम परेशानियों का सामना कर रहे आम नागरिकों ने राजधानी ला पाज़ में पिछले सप्ताह सड़कों पर मार्च किया और ''सब कुछ महंगा है'' के नारे लगाए।

इस बीच अर्थव्यवस्था मंत्री मार्सेलो मोंटेनेग्रो ने मंगलवार को कहा, ''डीजल की बिक्री सामान्य होने की प्रक्रिया में है।''

बोलीविया के राष्ट्रपति लुइस आर्से ने भी बार-बार ईंधन की कमी को खत्म करने के लिए बुनियादी वस्तुओं की कीमतें कम करने का आश्वासन दिया है।

हालांकि बोलीविया के लोगों का कहना है कि आर्से की छवि केवल मौजूदा संकट के कारण खराब नहीं हुई बल्कि सरकार द्वारा संकट को स्वीकार न करने की वजह से अधिक खराब हुई है।

आर्से ने 10 नवंबर को भी एक बार फिर देशवासियों से वादा किया था कि वह 10 दिन में ''इस मुद्दे को हल करेंगे।''

होसूर रोड के सुमतिनाथ जैन मंदिर पर विधि विधान से हुआ ध्वजारोहण

लाभार्थी बोथरा परिवार ने फहराई अमरध्वजा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के होसूर रोड के बोमसंद्रा क्षेत्र में स्थित सुमतिनाथ जैन मंदिर की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर 17वां ध्वजारोहण का मंगल कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वर्षगांठ के मौके पर शांतिनगर जैन मंदिर से बोमसंद्रा मंदिर तक श्रद्धालु बस के द्वारा रवाना हुए।

मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं व लाभार्थी परिवार द्वारा 18 अभिषेक का धार्मिक अनुष्ठान किया तथा सत्तरभेदी पूजा की गई। पूजा के बाद दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में मंदिर के शिखर पर पूरे विधि विधान से ध्वजारोहण किया गया।

विधिकारक तुषारगुरुजी ने मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि द्वारा कायमी अमरध्वजा के लाभार्थी मलबरी सिल्कस के राजेन्द्रकुमार त्रिलोककुमार बोथरा परिवार के सदस्यों ने मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराई।

प्रदर्शन

इंफाल ईस्ट में हज़ारों महिलाओं ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन करते हुए।

हसीना के खिलाफ आईसीसी में मुकदमा चलाना चाहता है बांग्लादेश

ढाका/भाषा। बांग्लादेश पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत (आईसीसी) में मुकदमा चलाना चाहता है जबकि मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों पर वह घरेलू न्यायाधिकरण में मुकदमे का सामना कर रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

मुख्य सलाहकार की प्रेस इकाई के एक अधिकारी ने कहा, ''मुख्य सलाहकार यूनुस ने हसीना के मुकदमे के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत (आईसीसी) के अभियोजक करीम ए खान के साथ चर्चा की। खान ने यूनुस से उनके आधिकारिक जमुना आवास पर मुलाकात की।'' विवादास्पद नौकरी आरक्षण प्रणाली को लेकर अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद हसीना पांच अगस्त को देश छोड़कर भारत चली गई थीं। तीन दिन बाद, नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला था। अधिकारी ने कहा कि यूनुस ने बुधवार को खान के साथ अपनी बैठक के दौरान उन्हें बताया कि बांग्लादेश हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ आरोपों को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है।

हसीना और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के खिलाफ बांग्लादेश के आंतरिक अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) में दर्जनों मामले प्रक्रियाधीन हैं। हसीना के सहयोगियों में से कई जेल में हैं या देश और विदेश में फरार हैं। वहीं ढाका ने हसीना से भारत की वापसी के लिए इंटरपोल की मदद मांगी है। यूनुस ने पहले कहा था कि उनकी सरकार मुकदमे का सामना करने के लिए भारत से उनकी वापसी का भी प्रयास करेगी। हालांकि, आईसीसी अभियोजक ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अदालत आईसीटी-बीडी को सहयोग देना चाहेगा, जिसने अब तक हसीना और उनकी अवामी लीग पार्टी के कई शीर्ष सदस्यों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। प्रेस इकाई के अनुसार, दोनों ने अपनी चर्चा के दौरान रोहिंग्या संकट और उनके लिए मानवीय सहायता, म्यामां की स्थिति के साथ-साथ बांग्लादेश में जुलाई-अगस्त के जन आंदोलन के दौरान अत्याचारों के अभियोजन और जवाबदेही पर भी चर्चा की।

तीर्थयात्रा

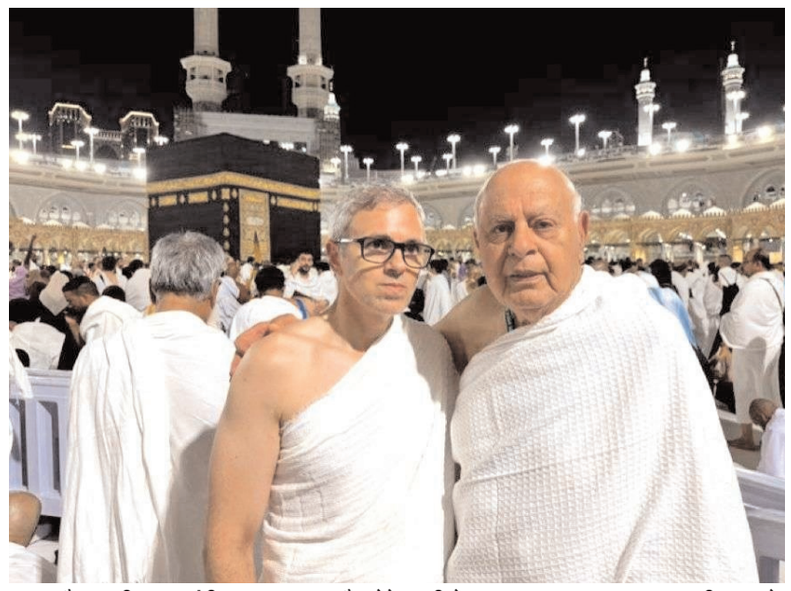

जम्मू और कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जेकेएनसी के अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला सऊदी अरब के मक्का में अपनी पवित्र उमराह तीर्थयात्रा के लिए ग्रैंड मस्जिद गए।

मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह मामले पर सिब्बल ने कहा

राजनीतिक लाभ के लिए देश को कहां ले जा रहे ?

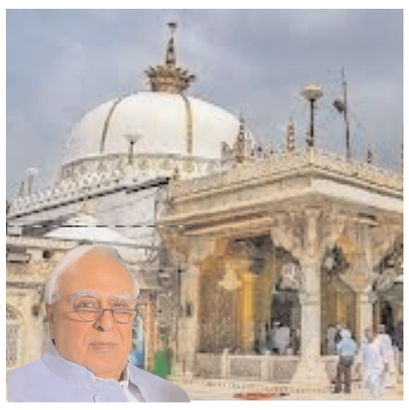

नयी दिल्ली। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में एक शिव मंदिर होने के दावे से जुड़े दीवानी मुकदमे में अजमेर की अदालत के नोटिस जारी करने के एक दिन बाद, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने बृहस्पतिवार को इस घटनाक्रम को चिंताजनक बताया और सवाल किया कि राजनीतिक लाभ के लिए देश को कहां ले जाया जा रहा है। वादी के वकील ने कहा कि अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को निर्देश दिया था कि एक दीवानी मुकदमे में तीन पक्षों को नोटिस जारी किया जाए। वाद में दावा किया गया है कि दरगाह में एक शिव मंदिर है।

सिब्बल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, चिंताजनक। नया दावा: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर। हम इस देश को कहां ले जा रहे हैं? और क्यों? राजनीतिक लाभ के लिए ? अधिवक्ता योगेश सिरोजा ने अजमेर में पत्रकारों को बताया कि मुकदमे की सुनवाई दीवानी न्यायाधीश मनमोहन चंदेल की अदालत में हुई। सिरोजा ने कहा कि दरगाह में एक शिव मंदिर होने का दावा करते हुए सितंबर में मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें वहां फिर से पूजा शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने कहा, हमारी मांग थी कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाये और दरगाह का किसी प्रकार का पंजीकरण है तो उसको रद्द किया जाए। उसका सर्वेक्षण एएसआई के माध्यम से किया जाए और वहां पर हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।

इससे कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के संभल में इसी तरह के मामले को लेकर हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी और पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए थे।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंदू आध्यात्मिक नेता की गिरफ्तारी की निंदा की

ढाका/भाषा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।दास को इस सप्ताह के शुरू में देशद्रोह के आरोप में हिरासत में लिया गया था।शेख हसीना ने एक बयान में कहा, ''सनातन धर्म के एक शीर्ष आध्यात्मिक नेता को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।'' अवामी लीग की ओर से 'एक्स' पर किए गए एक पोस्ट में हसीना ने कहा, ''चटगांव में एक मंदिर को जला दिया गया है। इससे पहले, अहमदिया समुदाय की मस्जिदों, दरगाहों, चर्चों, मठों और घरों पर हमला किया ।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com